Postal Registration No. CHD/0107/2021-2023 Posted at MBU Chandigarh RNI No. CHABIL/2000/3469

हिन्दी/अंग्रेजी मासिक पत्रिका

दीन बन्धु सर छोटूराम

जाट लहर

जाट सभा सत्यमेव जयते

जाट सभा, चण्डीगढ़ के सौजन्य से प्रकाशित

वर्ष 21 अंक 10 30 अक्तूबर, 2021 मूल्य 5 रुपये

प्रधान की कलम से

जेलों की स्थिति में सुधार-अहम जरूरत

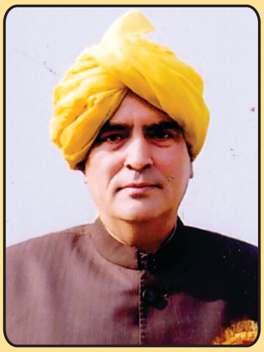

डा. महेन्द्र सिंह मलिक

जेलों की स्थिति में आजादी के इतने साल बाद भी कोई खास सुधार नहीं हुआ है। हकीकत में भारत की जेल व्यवस्था कैदियों की भीड़ को सीमित करने, जेल कर्मचारियों की कमी दूर करने और पर्याप्त संसाधन जुटाने जैसी समस्याओं से जूझ रही है। देश में कैदियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की भारत जेल सांख्यिकी–2019 रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में देश में जहां जेलों की संख्या एक हजार चार सौ बारह थी, वहीं 2019 में यह घट कर एक हजार तीन सौ पचास रह गई। 2019 में भारतीय जेलों में चार लाख अठहत्तर हजार कैदी थे, जो जेलों की वास्तविक क्षमता से साढ़े अठारह फीसद अधिक है।

जेलों में सजायाफ्ता कैदियों के मुकाबले विचाराधीन कैदियों की संख्या भी कम नहीं है। राष्ट्रीय क्राईम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2010 में राष्ट्र भर में जेलों में 2.90 लाख की क्षमता से अधिक 3.91 लाख कैदियों को रखा गया इनमें से दो तिहाई से अधिक कैदी ऐसे हैं जिनके मामले पुलिस अथवा कोर्ट में लंबित है मौजूदा समय में कुल कैदियों में से उनहत्तर फीसद कैदी विचाराधीन श्रेणी के हैं। जेलों में भीड़ बढ़ने की यह एक बड़ी वजह है और विचाराधीन कैदियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जेलों में कैदियों की बढ़ती संख्या आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस को दी गई अपार शक्तियों का परिणाम है न्याय प्रणाली में सुधार के लिए गठित मालीगढ़ कमेटी ने भी अपराधों के पुनः वर्गीकरण की सिफारिश की है। जिसके उपरांत वर्ष 2010 में अपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41 में संशोधन किया गया। जिसके अनुसार 7 साल से अधिक की सजा वाले गंभीर अपराधों में ही अपराधी को गिरफ्तारी किया जाना चाहिए। इसके साथ ही न्यायिक अधिकारियों को भी यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि पुलिस द्वारा की जाने वाली सभी गिरफ्तारियां जरूरत पर आधारित है। अपराधियों को छोटे–मोटे मामलों में जेल में विचाराधीन रखने का कोई औचित्य नहीं है अगर वह सुरक्षा तथा जमानती ब्रांड भरने को तैयार है बेवजह कैद को कम्पाऊड़ उत्पादक माना गया है। इसलिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता 320 के अनुसार इसके अंतर्गत कंपाउडेबल अपराधियों की सूची का विस्तार किया जाना चाहिए और अधिक केसों का पुनः वर्गीकरण करके जमानती अपराधों में अंकित किया जाना चाहिए। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 436 ए में भी किसी मुकदमे में आधी से अधिक सजा भुगत चुके कैदी की रिहाई का प्रावधान है। धीमी न्यायिक प्रक्रिया के कारण जमानत पर रिहाई पा चुके हजारों कैदी जमानत और जमानत ब्रांड न मिलने के कारण जेलों में रहने पर मजबूर है।

भारतीय जेलें सिर्फ कैदियों की भीड़ से ही नहीं, कर्मचारियों की कमी से भी जूझ रही हैं। देशभर में जेल कर्मचारियों के स्वीकृत सत्तासी हजार पांच सौ निन्यानवे पदों में से छब्बीस हजार आठ सौ बारह पद खाली पड़े हैं। वहीं, जेलों में कैदियों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए नियुक्त होने वाले स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या भी लगभग दो हजार ही है, यानी एक चिकित्साकर्मी पर लगभग ढाई सौ कैदियों की स्वास्थ्य जांच का भार है। इस मामले में सबसे बुरी स्थिति पश्चिम बंगाल की है, जहां एक स्वास्थ्यकर्मी को औसतन नौ सौ तेईस कैदियों की सेहत का हाल लेना पड़ता है।

हरियाणा की जेलों में भी आवश्यकता से अधिक कैदी हैं, जिसमें रेवाड़ी जेल में निर्धारित संख्या से तकरीबन दोगुनी संख्या में कैदी मौजूद हैं। सीएचआरआई ने हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एचएएलएसए) के तत्वावधान में यह अध्ययन किया। अध्ययन में महिला कैदियों को होने वाली समस्याओं मसलन तलाशी अभियान के दौरान ''अपमानित'' करने जैसी बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। हालांकि ये संतोष की बात है कि रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य के कैदियों की ''गंदी, मलिन और नारकीय'' स्थिति नहीं है। ऐसा पाया गया है कि जेलों में आधारभूत ढांचे, देखभाल और सफाई के इंतजाम हैं। ''इनसाइड हरियाणा प्रिजन'' नाम से अध्ययन में पाया गया कि पानीपत जेल में कैदियों संख्या 22.8 प्रतिशत जबकि रेवाड़ी जेल में यह 170 प्रतिशत अधिक है। टीम ने अध्ययन के लिये दिसंबर 2017 और मई 2018 के बीच 475 कैदियों, विधिक सेवा संस्थानों के प्रतिनिधियों और जेल अधिकारियों से बातचीत की। इनमें महिला कैदियों की संख्या 93, विचाराधीन कैदियों की संख्या 192, 122 पुरूष कैदी, 39 नाबालिग कैदी और 29 विदेशी नागरिक हैं। राज्य की 19 जेलों में 19,000 कैदी हैं जिनमें अंबाला का एक और हिसार में दो केंद्रीय कारागार हैं। अन्य 16 जिला जेल हैं। टीम ने इन सभी जेलों में जांच की। अध्ययन में अंबाला, हिसार, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, सिरसा, जींद, पानीपत, नारनौल और भिवानी जेलों में निर्धारित से संख्या कैदियों की संख्या अत्यधिक थी। गुरुग्राम की जेल में महिला कैदियों ने टीम को शिकायत की कि मोबाइल फोन और नशीला पदार्थ जब्त करने

शेष पेज–2 पर

जाट लहर पाठकों को दिपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

शेष पेज–1

के लिये होने वाले तलाशी अभियान के दौरान उन्हें "अपमानित" किया जाता है। प्राप्त आंकड़ों के आंकलन से कहा जा सकता है कि जेलों में बंद 80 फीसदी से अधिक कैदी मध्यम व गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों से होते हैं जोकि आधुनिक न्यायक प्रणाली का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं यानि आज एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति वकीलों की मार्फत अपने न्यायक मानवाधिकार की रक्षा नहीं कर सकता। अतः मानव अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसकी रक्षा व वर्चस्व के लिये सरकार को आवश्यक जेल सुधारों के लिये जरूरी अहम उठाने चाहिए।

भारत की जेलों में पर्याप्त चिकित्सा के अभाव में बड़ी संख्या में कैदी शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार पड़ते हैं। 2019 में विभिन्न बीमारियों से देशभर के जेलों में लगभग डेढ़ हजार कैदियों की मौत हुई, जिनमें चार सौ छह कैदी दिल की बीमारी के कारण, एक सौ नब्बे फेफड़े की बीमारियों से, इकसठ कैदी गुर्दे की बीमारी से, तियालीस कैदी एड्स से, इक्यासी कैदी टीबी से, अठहत्तर कैदी कैंसर से और छप्पन कैदी मस्तिशकाघात से मरे थे। जाहिर है, कैदियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। भारत सरकार ने इस दिशा में 2003 से 2008 तक 1800 करोड़ रूपए की राशि का जेलों के सुधार हेतु प्रावधान किया और ये राशि 75:25 प्रतिशत के आधार पर उपलब्ध तो कराई लेकिन इसका लाभ केवल कुछ राज्यों ने उठाया।

जेलों में कैदियों की भीड़ बढ़ना कोई नई समस्या नहीं है। लेकिन जेलों में कोरोना संक्रमण के खतरे के कारण कैदियों की भीड़ कम करने का दबाव है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में कैदियों की भीड़ कम करने के लिए सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि जिन कैदियों को पिछले साल महामारी के मद्देनजर पैरोल दी गई थी, उन्हें फिर से यह सुविधा दी जाए। गौरतलब है कि पिछले साल उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद कुल अड़सठ हजार कैदियों को पैरोल पर रिहा किया गया था। हालांकि जेलों में दबाव को कम करने का यह एक तात्कालिक उपाय है, लेकिन धीरे–धीरे सरकार को 'जेल सुधार' की ओर भी कदम बढ़ाने की जरूरत है, ताकि कैदियों की संख्या को सीमित करने का मकसद पूरा हो जाए।

इस मामले में हम नीदरलैंड से सीख सकते हैं, जिसकी न्याय व्यवस्था की दुनियाभर में तारीफ होती है। प्रति एक लाख की आबादी पर वहां कैदियों की संख्या केवल इकसठ है। अपराधियों के प्रति बर्ताव का तरीका बदलने, मानवतापूर्ण व्यवहार करने और कैदियों को समाज के लिए उपयोगी बनाने पर जोर देने के चलते वहां अपराध दर में इतनी कमी आ गई है कि वहां जेलों को बंद कर उन्हें शरणस्थली और होटल आदि में तब्दील किया जा रहा है। 2014 के बाद वहां तेईस जेलों को बंद किया जा चुका है। अमेरिका तथा इंग्लैंड में भी दो तिहाई से अधिक अपराधिक मुकदमों का फैसला ट्रायल के बिना प्ली बारगेन द्वारा कर दिया जाता है।

देश में जेल सुधार की बुनियाद न्याय व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण से जुड़ी है। भारतीय न्याय तंत्र खुद ही न्यायाधीशों की कमी को दूर करने और लंबित मामलों के निपटारे की दोहरी चुनौती से जूझ रहा है। जब तक पर्याप्त जजों की नियुक्तियां नहीं की जाएंगी, तब तक त्वरित न्याय की आस पूरी नहीं होगी। जब समय पर न्याय नहीं होगा, तो जेलें विचाराधीन कैदियों से भरी रहेंगी। न्यायाधीशों की कमी से जूझ रही अदालतों में लंबित मामले दिन–ब–दिन बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ों में अभी तीनों स्तर की अदालतों में करीबन साढ़े चार करोड़ मामले लंबित हैं।

जेल व संबंधित प्रशासन राज्य सूची में आता है जो कि संविधान में लिस्ट 2, शेड्यूल 8 के अंतर्गत वर्णित है जिसके तहत कानून के शासन द्वारा राष्ट्र, जेलो व आपराधिक न्यायिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली को सवैधानिक तंत्र द्वारा संचालित किया जाता है। राष्ट्र में जेल प्रशासन के संचालन हेतु काफी प्रसार प्रभावशाली व महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसको तर्कपूर्ण व प्रभाव प्रभावी ढंग से लागू करना आवश्यक है जैसे–जेल एक्ट 1894, कैदी अधिनियम 1900, कैदी ट्रांसफर अधिनियम 1950 तथा कैदी (न्यायालय में उपस्थिति) अधिनियम 1955 चार मुख्य जेल कानून प्रचलित है। इसके साथ ही जेल प्रशासन के संचालन व मजबूती के लिए भारतीय दंड संहिता 1860, अपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973, अपराधिक रोकथाम, नियंत्रण अधिनियम 1959, राज्य जेल मैनुअल के पैरोल नियम, मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993, कैदी प्रत्यार्पन अधिनियम 2003, किशोर न्याय (देखभाल तथा सरक्षण) 2000 आदि न्याय के प्रावधान है। इसके साथ ही स्वतंत्रता पूर्व तथा बाद में जेल सुधार हेतु विभिन्न समितियों व कार्यकारी समूहो – अल इंडिया जेल कमेटी (1919 और 1920), जेल पूछताछ समिति 1940, यू एन विशेषज्ञ–डब्लू सी जेल प्रशासन 1951–52, अल इंडिया जेल मैनुअल कमेटी 1957 आदि बनाई गई।

जेल प्रबंधन का अभी तक जेलों के अंदर व बाहर अनुशासन तथा सुरक्षा पर ही विशेष ध्यान रहा है जबकि सुधारात्मक गतिविधियों हेतु केवल 2 प्रतिशत जेल स्टाफ है। अतः जेलों को टार्चर सेल की बजाय सुधार व पुनर्वास केंद्र

के तौर पर विकसित किया जाना चाहिए और जेल प्रबंधन में सुधार व परिवर्तन हेतु सकारात्मक कार्य किए जाने की जरूरत है। जेलों में सजायाफ्ता कैदियों अथवा कार्य करने के इच्छुक अपराधियों के लिए काम करने की पर्याप्त सुविधाएं जुटाई जाए, कैदियों के लिए आसान प्रोबेशन, पैरोल व फरलो आदि की सरल व्यवस्था की जाए और जरूरत अनुसार कानून में संशोधन किया जाए, जेल साक्षात्कार प्रणाली को फिर से डिजाइन किया जाए, कैदियों के लिए बाहरी दुनिया से संपर्क करने की सुविधा बढ़ाई जाए, एन. आई.ओ.एस तथा अन्य शिक्षण संस्थानों द्वारा उपलब्ध शिक्षा कार्यक्रमों को लागू किया जाए तथा अधिकतम खुली जेलों व कैंपो आदि की व्यवस्था की जाए।

डॉ० महेंद्र सिंह मलिक
आई.पी.एस. (सेवा निवृत)
पूर्व पुलिस महा निदेशक हरियाणा,
प्रधान अखिल भारतीय शहीद सम्मान संघर्ष समिति एवं
जाट सभा, चंडीगढ़ व पंचकूला

लखीमपुर पर गंभीर नहीं उत्तर प्रदेश सरकार

– कमलेश भारतीय की कलम से

यह मेरा कहना नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लखीमपुर खीरी कांड की जांच को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर नहीं। तभी तो अभी तक कुल 164 गवाहों में से मात्र 44 के ही बयान दर्ज क्यों हुए ? साफ बात है कि सरकार इतनी धीमी जांच चला कर विधानसभा चुनाव तक इसे ठंडे बस्ते में डाल देना चाहती है। अभी तक तो केंद्रीय राज्य मंत्री महोदय का इस्तीफा तक नहीं लिया गया केंद्र सरकार की ओर से। सीधी बात है कि वे जांच को प्रभावित करने के लिए खुले छोड़ दिये गये हैं।

लखीमपुर खीरी कांड के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार बैकफुट पर है। पहले तो विपक्ष को वहां पीड़ित परिवारों से मिलने ही न दिया जब प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा हिरासत में लिये जाने के बाद भी डटे रहे तब कहीं जाकर मिलने की इजाजत मिली नहीं तो कह रहे थे कि इसे टूरिस्ट प्लेस न बनाइए। उधर अखिलेश यादव को भी घर पर ही घेर लिया गया था जबकि जयंत को भी हिरासत में ले लिया गया था। बाद में पांच पांच प्रतिनिधियों के साथ जाने की इजाजत दी गयी। अब वही हाल आगरा के लिए प्रियंका गांधी के साथ किया गया। पहले हाइवे पर रोक लिया और बाद में पांच लोगों के प्रतिनिधिमंडल के साथ जाने की इजाजत दे दी। वैसे प्रियंका गांधी ने रोके जाने पर कहा कि क्या वे रेस्ट हाउस को ही अपना घर मान लें ? किसी भी जगह विपक्ष को विरोध करने के अधिकार से वंचित करने की कोशिश क्यों करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ? अब तो सुप्रीम कोर्ट भी सवाल कर रहा है कि जांच की रतार इतनी सुस्त क्यों ?

रोज़ गोदी मीडिया में अपनी सरकार की रिकार्डिड उपलब्धियां गिनवाने से क्या लखीमपुर खीरी कांड की याद भूल जाएगी ? क्या लखीमपुर खीरी कांड धुल जायेगा ? विपक्ष इतनी आसानी से इसे भुलाने न देगा। क्या सन् 84 के दिल्ली दंगे भुला दिये गये ? विपक्ष यानी आज के सत्ताधारी दल ने इसे भूलने दिया ? तो आप जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहे ? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को पद से मुक्त क्यों नहीं कर देते साहब ?

लखीमपुर खीरी हो या आगरा एक नियम बना दीजिए कि पांच प्रतिनिधि ही जा सकते हैं। बार बार विपक्षी नेताओं को रोकना या विरोध न करने देना यह कोई लोकतंत्र की निशानी नहीं। लोकतंत्र की परम्पराओं का पालन कीजिए और जांच में सहयोग कीजिए।

कांग्रेस और पूर्णकालिक अध्यक्ष

आखिरकार सोनिया गांधी ने घोषणा कर ही दी कि कौन है पूर्णकालिक अध्यक्ष और कांग्रेस को कौन चला रहा है। यह दूसरी पार्टियों से ज्यादा अपनी पार्टी के जी 23 समूह के नेताओं को बताने की जरूरत थी जो इस चेतावनी के साथ बताई गयी कि मुझसे बात करने के लिए मीडिया के पास जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अपने सवाल लेकर आइए। बाहर जो भी जाना हो वह सीडब्ल्यूसी की संयुक्त बात होनी चाहिए न कि मीडिया ट्रायल। यही नहीं अब तो थोड़ा थोड़ा नवजोत सिद्धू को समझ आने लगा कि कौन है कांग्रेस हाईकमान। इस लिए इस्तीफा देने की रट कुछ कमज़ोर हुई है। वैसे हरीश रावत के पास अभी नहीं माने कि मैंने इस्तीफा वापस ले लिया है लेकिन अंदर ही अंदर वापसी को तैयार हो गये हैं। पहले तो अध्यक्ष पद पाने के लिए एक एक विधायक के घर गये जब पद मिल गया तो ऐसे ठुकरा दिया जैसा मांगा या चाहा भी न हो। चाहा तो मुख्यमंत्री पद था, मिला नहीं तो अध्यक्ष पद को थू कौड़ी कहने में देर न लगाई। जिस चन्नी की ताजपोशी करवाई उसी के विरोधी हो गये पंजाबियत के नाम पर और अब फिर हाईआन का आग बबूला चेहरा देखा तो जैसे थे, वैसे ही राजी हो गये। पर एक बात है जब खुद नवजोत सिद्धू किसी से संतुष्ट नहीं तो फिर ये किससे संतुष्ट हो सकेंगे ? इन्हें मनाना कौन सा आसान होगा ? बेटी कहती है कि पापा सिद्धू बेचौन रहते हैं पंजाब को लेकर। वह कैसा पंजाब होगा जो सिद्धू देने की दिन रात सोचते हैं ?

अब एक और घोषणा हाईकमान ने की है और वह घोषणा है कि 14 नवम्बर से 29 नवम्बर तक आम आदमी से जुड़ी बातों के लिए विरोध प्रदर्शन वगैरह किये जायेंगे। कम से कम बढ़ती महंगाई का मुद्दा तो उठाया जाये जोर शोर से। हालत यह है कि सब्जी की रेहड़ी लगाने वाला जब गली में आता है तो सब्जियों के भाव पर बात शुरू होते न होते सीधे मोदी तक पहुंच जाती है। अब यह हालत है

आम आदमी की। सब्जी रेहड़ी वाले को भी रोज़ गुस्से का शिकार होना पड़ता है आम आदमी के।

जो दिल्ली के पास बॉर्डर पर हुआ वह किसी भी तरह से प्रशंसनीय नहीं है। किसी को इतनी बेरहमी से मार देना जो सपने से भी बुरी मौत हो, कभी पैर काट रहे हो, कभी हाथ और कभी गर्दन पर जख्म दे रहे हो। इतनी निरशंसता ? तालिबान संस्कृति ? और शर्म से सिर झुका दिया मानवता का। स्वीकार भी कर लिया अपना अपराध बड़ी निडरता से।

सोनीपत के निकट अपने दोस्त की बहन का सुहाग उजाड़ देने वाले को फांसी की सज़ा दी गयी है। भाई अभी फरार है। क्या ऑनर किलिंग की बजाय माफ कर देना या भूल जाना सही न होता? अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, दुनिया से क्यों निकालते हो ? जीने का और अपनी मर्जी से जीने का अधिकार क्यों छीनते हो ? यह खुद ही बनाये हैं ऊंच नीच और खुद ही इनमें फंस कर रह गये हम लोग?

अब कमला पान मसाला नहीं पसंद

शुक्र है इस सदी के महानायक को अब कमला पान मसाला पसंद नहीं रहा। सभी तरफ से आलोचना होने के बाद अब बिग बी ने इसके पैसे तक लौटा दिये हैं और विज्ञापन में भी नहीं दिखेंगे। यह सूचना खुद अमिताभ बच्चन ने दी है। शुक्र है देर आयद, दुरूस्त आयद। बहुत आलोचना सहनी पड़ी करोड़पति के बिग बी को तब कहीं जाकर समझ आई कि कमला पान मसाले का विज्ञापन नयी पीढ़ी के लिए अच्छा नहीं और ये प्रतिबंधित है। सदी का महानायक इतना मासूम कि जानते ही नहीं कि कमला पान मसाला हो या कोई और पान मसाला ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। विभाग ने भी बिग बी को चेताया था लेकिन किस रौब में आकर रणबीर सिंह के साथ विज्ञापन कर लिया और फजीहत करवाई सो अलग।

मुझे ऐसे समाचारपत्र में काम करने का सौभाग्य मिला जिसके संस्थापक दयाल सिंह मजीठिया ब्रह्म समाज से जुड़े थे और उन्होंने शराब ब पान सिगरेट के विज्ञापन न लेने का फैसला किया था जो आज तक लागू है। जहां बिग बी जैसे आदर्श को समाज की चिंता करनी चाहिए वहीं समाचारपत्र की भी भूमिका है कि नयी पीढ़ी को ऐसे विज्ञापनों से गुमराह न करे। याद दिला दूं आपको कि बैडमिंटन चौंपियन गोपीचंद फुलेला ने शराब के विज्ञापन को इंकार कर दिया था। इसे कहते हैं आदर्श। ऐसे ही खिलाड़ी होने चाहिएं न कि हर किसी विज्ञापन से पैसा कमाना इनका उद्देश्य होना चाहिए। चाहे फिल्मी सितारे हैं या फिर खिलाड़ी युवा पीढ़ी के ये आदर्श होते हैं और उन जैसा ही बनना चाहते हैं। रजनीकांत की सिगरेट जलाने की स्टाइल कितने युवकों ने अपनाई ? खुद प्राण कितनी तरह से अलग अलग किरदार निभाते थे। इसके बाबजूद सामाजिक जिम्मेवारी भी कोई चीज़ है। नशों के विरूद्ध अभियान में फिल्मी सितारों को शामिल होना चाहिए और होते भी हैं तो कम से कम पानी मसाले, शराब या सिगरेट के विज्ञापन से भी दूर रहना चाहिए।

शुक्र है बिग बी ने विज्ञापन वापिस लेने को कह दिया और पैसे भी लौटा दिये। सदी के महानायक से भविष्य में भी ऐसी ही उम्मीद है कि ऐसे विज्ञापनों से दूरी बनाये रखेंगे। सबसे ज्यादा शर्मिंदा किया पहलवान सुशील कुमार ने जिसने पहलवानी को गलत कामों के लिए उपयोग करना शुरू किया और हश्र भी वैसा ही हुआ।

बंदूक, शिक्षा और हमारी सोच

जम्मू कश्मीर के ताज़ा घटनाक्रम में कश्मीरी पंडित माखन लाल बिंद्रू को आतंकवादियों ने मार गिराया। वे माखन लाल जो सन् 1990 में भी कश्मीर से पलायन कर कहीं नहीं गये और अपनी केमिस्ट शॉप चला कर अपनी सेवायें हर वर्ग को देते रहे। लगभग तीस साल आतंक के साये में इतनी निडरता से जिये कि अपनी संतान को भी वही निडरता का पाठ पढ़ा गये तभी तो उनकी बेटी श्रद्धा बिंद्रू ने जो कहा वह बहुत सोचनीय है, विचारणीय है और महत्त्वपूर्ण है। क्या बंदूक बड़ी है या शिक्षा ? शिक्षा बड़ी है। बंदूक किसी काम नहीं आती मुसीबत में। यही बात श्रद्धा बिंद्रू ने कही कि आपको नेताओं ने हाथों में बंदूक थभाई तो मेरे पिता ने दी शिक्षा। आज मैं एसिस्टेंट प्रोफेसर हूं। आओ मेरे साथ बहस करो। इन नेताओं के हाथों में न खेलो। शिक्षा आपको सब कुछ देती है और बंदूक आपसे सुख चौन छीन लेती है। मेरे पिता ने मुझे कुरान भी पढ़ाया और कुरान में कहीं हिंसा करने की बात नहीं। मेरे पिता को आपने मारा जरूर लेकिन वे जिंदा रहेंगे और उनकी सोच भी। आखिर कुरान इसकी इजाजत नहीं देता। कुरान किसी के हाथ में बंदूक नहीं थमाता। कुरान हो या कोई भी धार्मिक ग्रंथ वह हिंसा नहीं पढ़ाता। दुनिया का हर धार्मिक ग्रंथ प्रेम ही पढ़ाता हे और प्रेम ही बांटने की शिक्षा देता है तो श्रद्धा ने ललकारा कि आओ मेरे हाथ बहस करो।

सवाल उठता है कि यदि इतना साहस हर नागरिक में आ जाये तो आतंकवाद की जड़ें हिल जायें। जब आतंकवादी भाग निकलने की सोचें तब इन्हें सब लोग घेर लें तो ये क्या कर पायेंगे और कितने लोगों को मार सकेंगे ? ये तो बंदूकधारी हैं और यही इनकी ढाल है लेकिन इतना हौसला नहीं कि भीड़ के आगे टिक सकें।

एक बेटी की ललकार को सुनने ही नहीं बल्कि समझने की जरूरत है। ये वही लोग हैं जिन्हों ने दंगल की प्रतिभाशाली अभिनेत्री को भी घर बंद रहने पर मजबूर कर दिया। क्या वह अपनी कला को मार दे ? क्या आतंकवाद का यह तालिबानी चेहरा नहीं ? बताया जा रहा है कि चार हजार कश्मीरी पंडित कश्मीर लौट चुके थे और उनके हौंसला पस्त करने के लिए माखन लाल को चुना गया यानी टार्गेट बनाया गया। वे नहीं चाहते कि कश्मीरी पंडित अपने घरों में लौटें। श्रद्धा जैसी बेटी ने जैसे ललकारा है, ऐसे ही सबको ललकारना होगा तब कोई राह निकल सकेगी।

सुप्रीम कोर्ट, किसान और धान

सुप्रीम कोर्ट ने फिर किसानों को कहा है कि आपको लगातार दस माह हो गये दिल्ली के रास्ते रोके हुए और आप अब शहर में घुसना

चाहते हो ? इसकी इजाजत आपको नहीं मिल सकती। जब किसानों के रास्ते में कील ठोक दिये गये थे तब कहां थे सरकार ? शायद आपने ही कहा था कि प्रदर्शन का अधिकार है। लोकतंत्र में अधिकार है भी और उस अन्नदाता को तो है ही जो धूप, बरसात और सर्दी यानी हर मौसम को सहकर अपने शरीर पर आपके लिए अन्न पैदा करता है और आप कहते हो कि शहर में घुसने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अभी अभी एक मज़ेदार टिप्पणी सोशल मीडिया पर पढ़ी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रामायण काल में पटाखे नहीं थे तो जवाब बड़ा ही मज़ेदार आया कि रामायण काल में तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं था। सही बात है अन्नदाता भी सुप्रीम कोर्ट से पहले है। शिल्पा शेट्टी की तरह सुपर से ऊपर कहने की हिमाकत नहीं कर सकता।

इधर किसान आंदोलन और भारत बंद के बाद से राकेश टिकैत ने कहा कि उन लोगों के मुंह बंद कर दिये जो कहते थे कि किसान आंदोलन पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में ही है। किसान आंदोलन का असर आने वाले विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। इसी डर की वजह से तो कैप्टन अमरेंद्र सिंह भाजपा में शामिल न हो पाये। द्वार पर जाकर लौट आए। यही कारण है कि दूसरी प्लॉन लागू की जा रही है कि पंजाब में कांग्रेस सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए बुला कर राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश की जाये। अपने शाह के पास कमी नहीं प्लॉन की। फिर कैप्टन अमरेंद्र सिंह से अलग पार्टी बनकर भाजपा के लोगों को, चहेतों को टिकट दिये जायेंगे। इस तरह इसे प्लॉन सी भी कह सकते हो।

पर किसान का क्या ? उसका तो धान खरीदने का कोई सिस्टम नहीं बनाया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों व कमेरे वर्ग से मुंह मोड़ लिया। धान की सरकारी खरीद के अभाव में किसान प्राइवेट एजेंसियों के हाथों लूट रहे हैं या लुटने को मजबूर हैं। अभय चौटाला भी कह रहे हैं कि अन्नदाता की बेकद्री की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी रास्ते खुलवाने के लिए अमित शाह से मिलने जायेंगे। धान की खरीद प्राथमिकता नहीं है। शायद सुप्रीम कोर्ट धान की खरीद पर भी कुछ कहेगा या सिरसा शहर में घुसे चले आ रहे किसान को ही रोकता रह जायेगा ?

चन्नी हो गये परदेसी और कांग्रेस की बना दी सर्कस

जो घटनाक्रम कल हुआ और जिस तेज़ी से हुआ उस पर इतना ही सूझ रहा है कि चन्नी भी हो गये परदेसी सिद्धू ने कांग्रेस की बना दी कॉमेडी सर्कस। वैसे यह अजब संयोग है जब कांग्रेस को कुछ ढंग की कवरेज मिलनी होती है तब ऐसी बात सामने आ जाती है कि वह कवरेज न होकर कोई और बात उछल जाती है। अब देखिए चरणजीत सिंह चन्नी एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बना कर कांग्रेस वाहवाही लूटने और अकाली बसपा गठबंधन को पीछे छोड़ना चाहती थी लेकिन हरीश रावत ने बयान दे दिया कि अगले साल चुनाव में नवजोत सिद्धू कांग्रेस का चेहरा होंगे और सारा काम और नाम मिट्टी में मिला दिया। अब हरीश रावत कहां हैं ? कौन बनेगा अगले साल कांग्रेस का पंजाब में चेहरा ?

क्या सिद्धू ने कांग्रेस को कॉमेडी सर्कस ही बना डाला? सवाल सहज ही उठता है। मात्र 68 दिन पहले एक मजबूत पार्टी और मजबूर सरकार को बदल दिया कांग्रेस हाईकमान ने। कैप्टन अमरेंद्र सिंह के अनुभव और चेहरे को कह दिया –सॉरी। नवजोत सिद्धू की मन की मुराद फिर भी रही अधूरी और चरणजीत सिंह चन्नी को मिल गया लॉटरी में जैसे मुख्यमंत्री पद। इससे पहले कि नवजोत सिद्धू चन्नी को डम्मी मुख्यमंत्री साबित कर पाते चन्नी ने अपने फैसले लेकर चौंका दिया। और लो चन्नी भी परदेसी हो गये सिद्धू के लिए जिनका हाथ पकड़ कर गुरुघर गये थे उन्हें छोड़ते एक पल नहीं लगाया।

जो कवरेज कांग्रेस को कन्हैया कुमार को कांग्रेस में शामिल करने पर मिलने वाली थी ऐन मौके पर नवजोत सिद्धू ने इस्तीफा देकर उसे मामूली बना दिया। जिग्नेश ने भी शामिल होना था । आए भी और तिरंगा पटका भी पहन लिया लेकिन तकनीकी कारण से वैचारिक समर्थन देने की घोषणा की। इस तरह सिद्धू ने सारे कांग्रेस शो पर पानी फेर दिया और रणदीप सुरजेवाला पत्रकारों को सिर्फ कन्हैया कुमार तक केंद्रित रहने का आग्रह करते रहे और सिद्धू के बारे में सवालों से बचते रहे। सिद्धू ने क्या सचमुच कांग्रेस को कॉमेडी शो बन कर रख दिया पंजाब में ? कांग्रेस हाईकमान को क्या मिला? न कैप्टन अमरेंद्र सिंह न नवजोत सिद्धू। सिद्धू हर बार पंजाब और पंजाबियत के नाम पर समझौता न करने की बात कह कर अलग हो जाते हैं। वह कौन सा पंजाब है और कैसी पंजाबियत है सिद्धू जी ? अब कितनी बार एक डॉयलाग चलेगा या हिट होगा ?

दुविधा में दोऊ गये ....
कहने को बहुत कुछ था, अगर कहने पे आते,,,,

हां, जो हरियाणा के साथ पंजाब की तुलना कर रहे थे खासतौर पर कैप्टन अमरेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर वे खामोश हो गये हैं इस अंत को देखकर।

विश्व भुखमरी सूचकांक में नीचे लुढ़कना चिंताजनक

– शंभू भद्रा

एक तरफ सरकार की ओर से अर्थव्यवस्था की तेजी से रिकवरी की बात कही जा रही है, महामारी के दौरान 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त अनाज पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, दूसरी तरफ भारत एक साल में ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) में सात पायदान नीचे खिसक गया है। विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत का पाकिस्तान (92), बांग्लादेश (76), नेपाल (76), म्यांमार (71) से भी पीछे होना चिंता पैदा करता है। भारत 116 देशों के जीएचआई 2021 में 101वें स्थान पर खिसक गया है।

पिछले साल 2020 में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में लोग कोविड–19 और इसके चलते लगाई गई पाबंदियों से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। आयरिश एजेंसी कंसर्न वर्ल्डवाइड और जर्मन आर्गनाइजेशन वेल्ट हंगर हिल्फ़ की संयुक्त रूप से तैयार की गई रिपोर्ट में भारत में भुखमरी के स्तर को श्चिंताजनक बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, पड़ोसी देश जैसे नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी अलार्मिंग हंगर कैटेगरी में हैं। चीन, ब्राजील और कुवैत सहित अठारह देशों ने टॉप रैंक हासिल किया है। इनका जीएचआई स्कोर पांच से कम है। भारत का स्कोर 27.5 है। सूची में भारत से पीछे केवल पापुआ न्यू गिनी, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, कॉन्गो, मोजाम्बिक, सिएरा लियोन, तिमोर लेस्टे, हैती, लाइबेरिया, मैडागास्कर, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, यमन, सोमालिया आदि जैसे निहायत गरीब देश हैं। जीएचआई स्कोर की गणना अल्पपोषण, पांच साल तक के कम वजन व कम कद के बच्चे, और बाल मृत्यु दर जैसे चार संकेतकों के आधार पर की जाती है।

चार संकेतकों के मूल्यों के आधार पर 0 से 100 तक के पैमाने पर भुखमरी को निर्धारित किया जाता है। जहां 0 सबसे अच्छा संभव स्कोर (भूख नहीं) है और 100 सबसे खराब है। भारत ने वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत के लिये एक कार्ययोजना विकसित की है। वर्तमान रिपोर्ट को देख कर साफ लगता है कि देश 2022 तक कुपोषण मुक्त नहीं हो पाएगा। सरकार की ओर से पीडीएस, अंत्योदय, पोषण आहार, जरूरतमंदों को मुफ्त व सस्ता अनाज आदि जैसे 50 से अधिक योजनाएं गरीबों के लिए चल रही हैं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित नवीन मापदण्ड अनुसार राज्य सरकारों द्वारा आंगनवाडी केन्द्रों के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती/धात्री माताओं, अतिकम वजन के बच्चों को प्रति हितग्राही प्रतिदिन पूरक पोषण आहार दिये जाने का प्रावधान किया गया हैं।

चिंता की बात यह भी है कि इन सबके बावजूद भारत का भुखमरी सूचकांक में सात पायदान गिरना योजनाओं के संचालन पर सवाल उठाता है। भारत के शिशु मृत्युदर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। भारत में पांच साल से कम आयु के बच्चों की मौत की दर 2021 में प्रति हजार 33 है, जबकि 2019 में 28 थी, 1990 में यह दर 89 थी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 2015 में 93 वें, 2016 में 97 वें, 2017 में 100 वें, 2018 में 103 वें, 2019 में 102 वें, 2019 में 94वे और 2020 में 101वें स्थान पर रहा। यं आंकड़े बता रहे हैं कि भारत पांच साल कम उम्र के बच्चों के पोषण की दिशा में बहुत तेजी से प्रगति नहीं कर रहा है। सरकार ने बेशक भारत के जीएचआई के आंकड़ों पर संदेह जताया है, लेकिन आम बजट 2021 में भारत सरकार ने महिलाओं व बच्चों के पोषण के लिए 2700 करोड़ रुपये आवंटित किया है, पिछले साल के बजट में यह रकम 3700 करोड़ रुपये थी। भारत में प्रति वर्ष 2.5 करोड़ बच्चे का जन्म होता है। इस हिसाब से सालाना आवंटित बजट काफी कम है। इसके साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र के संचालन में भ्रष्टाचार की खबरें भी सामने आती है। ऐसे में भारत सरकार पांच साल कम उम्र के बच्चों के पोषण की दिशा में बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है।

बिजली संयंत्रों को बनी रहे कोयले की आपूर्ति

– विनोद कौशिक

देश में अगर बिजली संकट गहराएगा तो अर्थव्यवस्था को गहरी चोट लगेगी। कोरोना महामारी से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौट रही है। इसके लिए बिजली की आपूर्ति का सुचारू बने रहना जरूरी है। सरकारी कंपनी गेल और निजी कंपनी टाटा के गैस व कोयले की कमी से बिजली आपूर्ति बाधित होने के संदेश के चलते आने वाले वक्त में बिजली संकट होने की आशंका व्याप्त हुई है। गेल ने गैस आपूर्ति में कमी की चेतावनी दी थी तो टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने उपभोक्ताओं को एसएमएस भेजकर संभावित बिजली कटौती को लेकर सचेत किया था। यूं तो केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्री आरके सिंह और कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि देश में कोयला की कोई कमी नहीं है, इसलिए बिजली संकट गहराने का सवाल ही नहीं है। सिंह ने कहा कि संकट न तो कभी था, न आगे होगा। पहले की तरह कोयले का 17 दिन का स्टॉक नहीं है लेकिन हमारे पास चार दिन का स्टॉक है। प्रह्लाद जोशी ने कहा कि बिजली आपूर्ति बाधित होने का बिल्कुल भी खतरा नहीं है। बिजली उत्पादक संयंत्रों की जरूरत को पूरा करने के लिए कोल इंडिया के पास 24 दिनों की कोयले की मांग के बराबर 43 मिलियन टन का कोल का पर्याप्त स्टॉक है। लेकिन आंकड़े कोयले व गैस की आपूर्ति की कमी की ओर इशारा कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े बिजली उत्पादन संयंत्र ऊंचाहार के छह यूनिट में उत्पादन बाधित है। ऊंचाहार ताप बिजली संयंत्र से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरांचल को बिजली की आपूर्ति की जाती है। इस संयंत्र की किसी यूनिट के बंद होने से इन राज्यों में बिजली आपूर्ति पर असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के कुछ हिस्सों में बिजली की कटौती हो भी रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली,

राजस्थान, पंजाब, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोयले की कमी के कारण बिजली संकट और ब्लैकआउट के खतरे को देखते हुए इन राज्यों की सरकारों से केंद्र सरकार को लिखित पत्र भेजकर कोयले की आपूर्ति की मांग की है। भारत में कोयले से चलने वाले 135 पावर प्लांट में से आधे से ज्यादा ऐसे हैं, जहां कोयले का स्टॉक खत्म होने वाला है। इनमें से कई पावर प्लांट में केवल 2–4 दिन का ही स्टॉक बचा है। कोयला आधारित संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। भारत में इस्तेमाल होने वाली बिजली की आपूर्ति 71 फीसदी थर्मल पावर प्लांट्स के जरिए की जाती है। भारत ही नहीं चीन, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, रूस, लेबनान आदि देश पहले से ही ऊर्जा संकट का सामना कर रहे हैं। लेबनान अंधेरे में डूबा है। चीन की बढ़ती ऊर्जा भूख ने आपूर्ति तंत्र में असंतुलन पैदा कर दिया है।

यूरोप में नेचुरल गैस के उत्पादन में कमी, कोरोना के दौरान कोयले के उत्पादन की सुस्त रफ्तार, पिछले 18 महीने में जीवाश्म ईंधन को निकालने की दिशा में बहुत कम काम, चक्रवाती तूफानों के चलते खाड़ी देशों की कुछ तेल रिफाइनरी का बंद होना, रूसी गैस निर्यात में गिरावट, चीन और ऑस्ट्रेलिया के तनावपूर्ण संबंध व समुद्र में कम हवा चलने से दुनियाभर में ऊर्जा संकट गहरा गया है। भारत के संदर्भ में देखें तो आयातित कोयला कीमतों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की वजह से आयातित कोयला आधारित बिजली संयंत्र अपनी क्षमता के कम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। केंद्र सरकार को चाहिए कि राज्यों के बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति लगतार बनाए रखे, ताकि बिजली उत्पादन रुके नहीं। केंद्र को राज्यों की शिकायतें भी दूर करनी चाहिए।

'आपातकाल' से गुजरती कांग्रेस

–चेतनादित्य आलोक

कभी देश में आपातकाल थोपने वाली कांग्रेस आज स्वयं ही आपातकाल के दौर से गुजर रही है। हाल ही में वामपंथी से कांग्रेसी बने कन्हैया कुमार भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की नाव डूबने वाली है। 28 सितंबर को पार्टी में शामिल होने के बाद प्रेसवार्ता में 'कांग्रेस खतरे में है... अगर पार्टी नहीं बची तो...' जैसे बयानों के माध्यम से पार्टी की डूबती नाव को बचाने का अभिमान रखने वाले बड़बोले कन्हैया कांग्रेस जैसी बड़ी किन्तु बिखरी हुई पार्टी में आकर बड़ी जिम्मेदारियों को संभालने या कहें कि झपटने की इच्छा रखते हैं। बहरहाल, ऐसा मानना आधारहीन नहीं होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू की भांति बड़बोलेपन के कारण ही शायद कन्हैया कांग्रेस आलाकमान की पसंद बने। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बड़बोलापन अब कांग्रेस में तेज–तर्रार होने की गारंटी है, लेकिन यदि यह सत्य है तो 'जी 23' जैसे पुराने नेताओं पर यह बात क्यों लागू नहीं होती? राजद नेता शिवानंद तिवारी ने तो कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस आलाकमान को कन्हैया को ही पार्टी की कमान सौंप देनी चाहिए।

वैसे किसी ने अब तक यह पूछने का कष्ट नहीं उठाया कि कन्हैया कांग्रेस को कैसे बचाएंगे, क्योंकि स्वयं कन्हैया कितने योग्य और क्षमतावान हैं, यह भी किसी से छिपा नहीं है। देश की राजनीति में कन्हैया की अब तक की सबसे बड़ी पहचान अथवा उपलब्धि यह रही है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वे गिरिराज सिंह से 04 लाख 20 हजार मतों से पराजित हुए थे। साथ ही बेगुसराय सीट पर राजद के प्रत्याशी को हराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके परिणामस्वरूप फिलहाल बिहार में विधानसभा के कुशेश्वरस्थान एवं तारापुर सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस तथा राजद एक दूसरे के विरुद्ध प्रत्याशी उतारने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वस्तुतः राजद नेता तेजस्वी प्रताप यादव 2019 के लोकसभा चुनाव से ही कन्हैया को लेकर असहज रहते आए हैं। अब जबकि कन्हैया कांग्रेस नेतृत्व की पसंद बन चुके हैं तो राजद और कांग्रेस में खटपट शुरू हो गई। बहरहाल, कांग्रेस का संकट यह है कि पिछले साढ़े सात वर्षों में उसके लगभग 100 नेता पार्टी छोड़कर भाजपा या किसी दूसरी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। इसी प्रकार लगभग 150 विधायक एवं सांसद भी पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। कांग्रेस का आपातकाल यहीं नहीं थमा, बल्कि पार्टी में बचे हुए नेता–कार्यकर्ता, सांसद, विधायक इत्यादि अब भी या तो पूर्व की भांति निष्क्रिय ही रहने पर मजबूर हैं अथवा बोलने के कारण दरकिनार किए जा रहे हैं। इसके बावजूद कई बड़े और प्रभावशाली नेता अब जी–हजूरी को अलविदा कहते हुए खुली हवा में सांस लेना आरंभ कर चुके हैं। काश! ये कांग्रेसी थोड़ा पहले चेत जाते तो पार्टी को संजीवनी मिल जाती। वैसे अब राजनीतिक दलों में कलह–कोहराम, दांव–पेंच, उठा–पटक, खींच–तान और टूट–फूट सामान्य बात मानी जाती है, परन्तु आलाकमान की इच्छा को कानून मानने की परंपरा वाली कांग्रेस में पिछले कुछ वर्षों से जिस प्रकार टूट–फूट एवं खींचतान जारी है, और जिसे उसके वफादार सिपाही आंतरिक लोकतंत्र की संज्ञा देते नहीं थक रहे, उसे देख यदि कहा जाए कि कांग्रेस आईसीयू में चली गई है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि अब पुराने कांग्रेसियों को भी यह समझ में आने लगा है कि पार्टी के भीतर मचा कोहराम सामान्य घटना नहीं, बल्कि पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व के अशक्त होने का प्रतीक है।

यह तो स्पष्ट ही है कि आजकल किसी भी राजनीतिक सत्ता–संगठन की मजबूती इसी बात पर निर्भर करती है कि उसका सुप्रीम नेता अथवा आलाकमान अपने कार्यकर्ताओं–नेताओं को चुनाव जीताने में सक्षम हो तथा संगठन की बागडोर संभालने की योग्यता रखता हो। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि देशभर में कांग्रेस का घटता जनाधार ही उसकी सबसे बड़ी समस्या है। जाहिर है कि उसके नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को शायद अब ऐसा महसूस होने लगा है कि उसके नेता उसे चुनाव जिताने में सक्षम नहीं हैं, इसीलिए पार्टी के भीतर टूट–फूट जारी है और आलाकमान की नजर में नेता–कार्यकर्ता मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखाएं पार करने लगे हैं। वैसे तर्क दिया जा सकता है कि कई राज्यों में अब भी कांग्रेस की सरकारें मौजूद हैं, पर किसे नहीं पता कि उन राज्यों में वस्तुतः क्षेत्रीय नेताओं की राजनीतिक सूझबूझ और क्षमता के कारण ही कांग्रेस सत्ता में काबिज है। पंजाब को ही लें, तो वहां के मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने अपने बल–बूते पर ही चुनाव जीतकर स्वयं अपना ताज सुरक्षित रखा। हालांकि कैप्टन अमरिन्दर जैसे अनुभवी नेता के नेतृत्व वाली सरकार को कितनी नासमझी से गिराकर पार्टी ने अपनी ही छीछालेदर कराई, सबने देखा। पार्टी के नेता–कार्यकर्ता जिसे हाईकमान का मास्टर–स्ट्रोक बता रहे थे, तीन दिनों में ही उसकी बुरी तरह से धज्जियां उड़ती दिखीं। इसी प्रकार राजस्थान में अशोक गहलोत ने जैसे–तैसे सचिन पायलट को मनाकर तमाम खींच–तान के बावजूद अपनी साख बचाई। यह अलग बात है कि दोनों नेताओं में सुलह कराने में आलाकमान के नाकाम रहने के कारण गहलोत और पायलट के बीच का द्वन्द्व राख में दबी चिंगारी की भांति अब भी सुलग ही रहा है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सिंह बघेल और टीएस सिंहदेव ने मिल–जुलकर राज्य का सिंहासन प्राप्त किया। तात्पर्य यह है कि कांग्रेसी क्षत्रप अब चुनावी वैतरणी पार करने के लिए अपने आलाकमान के ऊपर निर्भर नहीं रहते। वे अब अपना हाथ जगन्नाथ की भूमिका में स्वयं ही अपना नेता बनकर उभरने लगे हैं। हालांकि चुनावी जीत–हार में निश्चित रूप से पार्टी की छवि आदि का भी प्रभाव अवश्य पड़ता है।

वर्तमान परिपेक्ष में स्वाभाविक ही है कि चुनावी राजनीति में घटती साख के कारण कांग्रेसी नेता–कार्यकर्ता अब आलाकमान को आंखें तरेरने लगे हैं। जाहिर है कि जो धरातल से जुड़ा हुआ हो... और जो अपने बलबूते पर सरकार बनाने–बिगाड़ने का खेल खेलने की क्षमता और साहस रखता हो, वह ऊपरी नेताओं का आदेश भला क्यों मानेगा। ऊपर का आदेश तो वैसे कार्यकर्ता–नेता मानते हैं, जिनका अपना जनाधार नहीं होता. .. जो चुनावी समर जीतने के लिए आलाकमान की कृपा पर निर्भर रहते हैं। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से पूर्व तक कांग्रेसी आलाकमान देश की चुनावी राजनीति में बड़े उल्टफेर करने की क्षमता रखता था, परन्तु अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। स्पष्ट है कि बदले हुए माहौल में यदि अपना हाथ जगन्नाथ की भूमिका वाले कांग्रेसी क्षत्रपों के ऊपर दिल्ली का आदेश थोपा जायेगा तो मध्य प्रदेश और पंजाब वाली स्थिति से पार्टी को बार–बार सामना करना ही पड़ेगा।

सिमटता गांव

– अंकुर सिंह

जीवन के तीस बसंतों को पार कर चुका हूं, जब कभी एकांत में बैठ कर बीते हुए वर्षों का अवलोकन करता हूं तो लगता हैं कि समय ने दीवार पर टंगे कैलेंडर को ही नहीं बदला, अपितु रिश्ते–नाते, संबंधों की परिभाषा भी बदल दिया।

मेरा बचपन भारतीय संस्ृति के उस गांव में बीता हैं। जहां बचपन से हमें सिखाया जाता रहा कि अमुक इंसान (चाहे वो किसी जाति, धर्म से आते हो) रिश्ते में सब तुम्हारे भाई–बहन, चाचा–चाची और दादा–दादी लगेंगे। उस समय के संस्ृति ने कभी उम्र में बड़ों को उनके नाम से संबोधित करना नहीं सिखाया हमें, बल्कि रिश्तों के डोर में बंधे रहना सिखाया। मेरे हमउम्र के नवजवानों को याद होगा की उनकी शरारत या अनैतिक गतिविधियों पर कोई पड़ोसी देख लेता तो वह उन्हें येन केन प्रकारेण उन्हें वही रोक देता था। इसपर सोचता हूं तो लगता है कि उस समय लोगों की ये मानसिकता नहीं थी कि ये लड़का, फलां व्यक्ति के घर का है, मेरा क्या जायेगा इसके बिगड़ने पर? अपितु उन्हे ये लगता था ये मेरे गांव का भविष्य है आज कुम्हार भांति थोड़ा गढ़ दिया तो कल पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा।

आज जब उसी गांव में अपनी छुट्टियां बिताने जाता हूं, तो प्रौढ़ उम्र के कुछ व्यक्तियों को युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे कुछ युवकों को उनके साथ अनैतिक गतिविधियों (नशा, चोरी, गलत शिक्षा) में लिप्त देखता हूं तो असहाय पीड़ा होती है, पर चाह कर भी वहां मौन रखना पड़ता है। इसका एक कारण ये भी है कि समय ने रिश्तों की परिभाषा बदल दिया। हमारे बचपन में हमारे गलतियों पर कोई भी परिचित हमें येन केन प्रकारेण (समझाते, डांटते और मारते थे) रोकते थे, और जब ये बात हमारे घर के अभिभावक को पता चलता तो वो भी हमें दंडित करते। आज के परिवेश का नवयुवक सुनना तो दूर हठ (बहस) कर जाते है, क्योंकि गांव का हर व्यक्ति

उनका चाचा,भैया, दादा, लगेगा ये भावना अब बचपन से नहीं दी जाती शायद उन्हें। उनके अभिभावक को यदि जानकारी होती है की उनके बच्चों को डांटा गया तो इसे वो अपनी शान के खिलाफ (शायद अभिभावक भूल जाते है कि चेतना का विकास समाज में ही होता है, और चेतना परिवेश के अनुसार निर्मित होती है) समझ लेते है। यदि बात ज्यादा बढ़ गई तो अभिभावक इसे अपनी शान पर लेकर मामले को मानवाधिकार, प्रशासन इत्यादि में भी ले जाते है। शायद इसलिए कुछ लोग चाहते हुए अपने पास–पड़ोस के नवजवानों को उनकी गलतियों का अहसास नहीं करा पाते और ना चाहते हुए भी आंख बंद वहां से निकल लेते हैं।

मैने बचपन का वह दौर भी देखा है जब चौपाले लगती थी, जाड़े के दिनों में जलती अंगीठी के पास लोग इकट्ठा हो जाते थे, एक कप चाय पर बड़ी से बड़ी समस्या सुलझ जाती थी। आजकल तो अधिकांश लोग अधिकतर मामले को आपसी संवाद से न निपटा, शासन या न्यायालय का दरवाजा खटकना पसंद करते है। जबकि वो ये भूल जाते है कि आपस के विवाद के चक्कर में अदालत में उनका समय बर्बाद होगा और उनके पास विकास हेतु सोचने करने का समय नहीं बचेगा। ये सच है कि ज्यादातर समस्या का समाधान आपसी सहमति ध्संवाद है (कई बार कोर्ट में सालों से लटके मामले भी राजीनामा से समाप्त होते है), इसी नजरिए से पूर्व प्रध ाानमंत्री अटल जी कश्मीर जैसे मुद्दे को बार–बार आपसी समझौता/संवाद से हल करने पर ज्यादा जोर देते थे। पूर्व राष्ट्रपति डॉ कलाम ने चित्रकूट के इलाकों में नानाजी देशमुख और उनके साथियों द्वारा ग्रामीण विकास प्रारूप हेतु बनाए संस्थान पर अपने एक बयान में कहा था किये संस्थान विवाद रहित समाज के निमार्ण में मदद करता है, क्योंकि चित्रकूट के आस–पास के लगभग अस्सी गांव के लोगों ने उस समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि किसी विवाद के स्थिति में उसके समाधान के लिए वो अदालत नहीं जायेंगे बल्कि आपसी सहमति/संवाद से उसका समाधान करेंगे।

विवाद यदि आपसी सहमति से निपटेगा तो रिश्ते अपनी मधुरता लिए आगे के लिए गतिमान रहेगा। यदि प्रशासन, न्यायालय से निपटेगा तो विवाद के निपटारे के साथ–साथ उन परिवारों के आपसी प्रेम सिमट जायेगा।

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी धीरे धीरे इस वाक्य का अर्थ समाज से विलुप्त होता जा रहा हैं। माना भौतिकवादी युग में विकास के लिए देश–विदेश के अलग–अलग स्थानों पर जीविकापार्जन हेतु रहना पड़ता है। पर अपने मातृभूमि से जुड़े रहने के साथ साथ उन्हें अपने स्तर से अपने मातृभूमि के विकास के लिए अपने गांव पर ध्यान भी देना चाहिए, ये नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना जैसे महामारी एवं अन्य हालत में मातृभूमि ने सभी को शरण दिया है।

महात्मा गांधी ने कहा था की ष्भारत की आत्मा गांवों में बसती है। इसलिए मेरा मानना है सरकार को चाहिए कि छठवीं कक्षा के बाद ये नियम बना देना चाहिए कि साल के इतने दिन (सरकार द्वारा निर्धारित संख्या) गांव में रहने पर (इसकी मॉनिटरिंग ग्राम स्तर के प्रशासनिक अधिकारी करें और उनके स्तर से इसका प्रमाण पत्र जारी हो) ही अगली कक्षा में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इस बहाने देश के नौनिहाल में बचपन से ही गांव के संस्कार अंकुरित होंगे और हम सब जानते है की बचपन के संस्कार जल्दी नहीं भूलते।

गांव की सीमा तो वही की वही रहेगी पर लोग आपस तक न सिमटे इसके लिए गांव स्तर के लोकगीत, त्योहार, परंपरा, रिवाज और भाषा के विकास हेतु सभी सरकारी एवम् गैर सरकारी संस्था सहित हमसब को साथ आना चाहिए, क्योंकि यहीं एक मध्यम है जो हमे एक धागे में पिरो कर रख सकता है। इसका एक सीधा उदाहरण देता है, गांव से 1500 किलोमीटर दूर यदि अपनी भाषा बोलते हुए कोई इंसान मिल जाता है तो हमें ऐसा प्रतीक होता है की रेगिस्तान में जलाशय मिल गया हो और फिर हम उससे इस कदर जुड़ने की कोशिश करते है जैसे हम वर्षों से जानते हो उसे।

America, China, Russia and India

- R.N. MALIK

Geographically, the planet earth looks to be a very strange entity. Its 67% surface area is drowned by a very vast and deep sheet of brackish water. There is an icy desert in Siberia of size greater than that of America .There is rainless Middle East in north Africa. Many more examples can be cited to support this argument. But looking at the human behaviour, the planet earth looks to be a mad house. Two World Wars were fought with an interregnum of just 20 years killing 60 million people(mostly young soldiers) for no fault of their own. After 1950, the Cultural Revolution in China took away the lives of 70 million people. Earlier, 'the great purge' in Russia had taken away the lives of 20 million people in 1917. Rivalries did not end with the end of the 2nd World War. It gave birth to a new Cold War between Russia and America that continued up to 1991. (Remember the horrors of the Vietnam war.) It has started again amongst America, China and Russia. Each of the three countries is arming itself to the teeth. Consequently, the entire world is now sitting on a volcano or a time bomb that can burst anytime to devastate the entire universe. Looking at the spread of Covid pandemic, it appears that China single handedly won the 3rd World War against the rest of the 188 nations with least mortalities. Three super powers are engaged

in unending high-tech devastating arms race. Other nations too are following their example due to neighbourly contentious conflicts like Israel with Arabs or Pakistan with India. Sale of arms is the net foreign exchange earner for Israel. There was naked dance of genocide in Syria with America and Russia brazenly supporting the two warring groups separately. U.N.O. did nothing to extinguish the raging fire. Earlier, similar scenes were witnessed during the break up of Yugoslavia into five small nations. U.N.O. has become the most effete organisation of the world. It has miserably failed to address the burning issues of the world like population explosion, poverty, terrorism, mad arms race and inherent danger to the World Peace. Likewise, people in the developing countries are suffering due to ethnic conflicts, home grown terrorism and unequal distribution of national wealth. Almost all countries are suffering from the irreparable damage due to degradation of environment and ecology, entry of pesticides and insecticides into the food chain and crop failures due to pest diseases. The spectre of Climate Change is hanging over the head of the entire humanity like the sword of Damocles. Thus the comity of 189 world nations no doubt globalised and economically integrated, presents a very fractured and fractious picture that makes the future of the entire humanity look very gloomy.

The root cause of most problems threatening the world peace are the rivalaries amongst the three countries, namely America, China and Russia, who are constantly engaged in stiff competition with each other to empower themselves to dominate the entire world. All the three countries have become super powers both in respect of economic strength and military might. Still they are constantly engaged in the process of surpassing each other by fair means or foul to attain a position of invincibility and international primacy. During the first Cold War period, the fight between Russia and America was essentially the fight between Capitalism and Communism and it divided the world nations into two blocks. A motley group of non-aligned nations were non-aligned only in name. Now the struggle among the three nations is to dominate the international market, achieving energy and cyber security, territorial gains and armed conflict invincibility. As a result, all the three countries are spending huge amount in manufacturing devastating arms. Presently, the main area under threat of conflicts between the two duper powers (US and China) is the Indo-Pacific region (read India).This conflict zone will shape the future geopolitical alignments of Asian and European countries.

America:-

The geographical area of America is 10 million square kms I.e. three times that of India. Her population is 31.2 crore i.e. one fourth of Indian population. Low population density is one reason for American prosperity. God has been extremely bounteous in providing natural resources to this country. She has the best democratic set up in the world and public administration is greatly decentralised. The central government takes care of foreign policy, defense, finance and trade. The rest is managed by the States. Private sector is the bulwark of the national economy. Even rail transport is managed by the private sector. The guiding principle is,"The government has no business to be in the business."

Presently, American economy occupies the top slot in the world with China as the poor second. Likewise, America excels other countries in the fields of education, scientific research, defense preparedness and space exploration.

America also started dominating the foreign policies of other countries after the second world war to create the strong American block to neutralise the expansionist influence of Russian communism and attain energy security. Finally, she succeeded in breaking up Soviet Union into 15 independent nations in 1991. Russian economy suffered a big jolt as a result of the break up. But Russia was still left with vast resources of oil and gas and their exports coupled with strong leadership(read dictatorship) of Vladimir Putin, Russia was able to resurrect her economy within a few years. But because of the break up and restoration of democracy in Balkan States, Russia is unable to play the preceding dominating role in the world affairs and her place has been taken up by China. Putin is still struggling to dominate the erstwhile Russian states to bring them under the Russian umbrella and form a hardcore geo-politic and geostrategic block. Finally, he has leaned towards China to neutralise the American influence (not dominance) in the world affairs.

Presently, America and China have engaged themselves in a geostrategic tug of war and are desperately trying to win over nations to bring them in their respective spheres of influence or camps and China is definitely running ahead of America in this race. Problem with America is that she only tries to convert other nations to become pro Americans and does not give them financial aid which the developing nations desperately need. However America does control the policies of the World Bank and other financial institutions and helps the pro American developing nations in securing loans quickly. China, on the other hand offers financial assistance to take up new infra projects. That is why underdeveloped countries are inching more towards China than America and Chinese clout is growing.

In 2oo4, Manishankar Ayyar was the Petrolium Minister in the UPA government. He had succeeded in finalising the project of laying the gas pipeline from Iran to India via Pakistan to ensure energy security. Condoleezza Rice, the then Foreign Minister of America rushed to India in December 2005 and pressurised the UPA government to drop that project by assuring American energy security in its place. Ayyar was replaced by Murli Deora in January 2006 as the new Petrolium Minister. But America forgot about her promise thereafter. The new Nuclear deal between India and America did not help India either because most nations decided not to set up nuclear power plants for fear of nuclear explosion . Now America has formed a strategic alliance with India, Japan and Australia (QUAD) to create a security ring around China to ensure unhindered sea routes in the Indo-Pacific region and neutralise the rise of Chinese influence in the ASEAN region. Another security ring has been created consisting of US,UK and Australia (AUKUS) to sharpen the penetrative power of Naval force in the Indo-Pacific region (the area extending from the Indian Ocean up to the western end of the Pacific Ocean) and US has supplied submarines to Australia under the tripartite pact. How this combination succeeds in safeguarding the region against Chinese thrust, only time will tell. One side effect of the QUAD alliance is that China has developed a hostile attitude towards India and has formulated a policy of needling India through occasional border skirmishes and helping Pakistan and Taliban governments financially. China on the other hand, woos nations by helping them with loans and initiating infrastructure projects in return of importing mineral resources at easy terms. Many countries do not accept Chinese offers because they know that China finally entangles the beneficiary states into a debt

trap. This happened in Pakistan recently. Pakistan sought the help of IMF to pay off the Chinese loan. But America put her foot down and dissuaded IMF not to grant loan to Pakistan.

Now the immediate points of conflagration between China and America are Taiwan(Taiwan raised a spectre of invasion by China when record number of Chinese jets entered the defence zone of Taiwan in the first week of October 2021), Hongkong, sea routes in the South China sea and territorial claims over large number of tiny islands. Strangely, American and Chinese economies are greatly integrated through large volumes of exports and imports. Chinese exports of goods and services to America in 2018 were worth $ 482 billion in exchange of American imports of $ 107 billion. 3.6 lac Chinese students are studying in American universities and their contribution to American GDP is by 15%.

American problem of energy security started mitigating in 2006 when some companies were able to fracture the Shale rock and extract oil and gas on commercial scale in east and west Texas. The production volumes of the two hydrocarbons are growing since then and now America is in a position to export both oil and gas to other countries. Presently, the gas production is 26.3 trillion cubic feet per year and oil production is 7.8 million barrels per day. Now American geologists have completed the mapping of shale rock (mostly 1.5 miles below the surface) in the entire country and the reserves are almost inexhaustible to meet American needs for another century. The discovery of these rare hydrocarbons has solved the triple problem of America namely, trade deficit, employment and excess carbon foot printing as the use of gas for power generation has reduced the use of coal by 37%. Now America can contest China in all walks of life with free mind and strong hand.

China:-

G7 group refers to the annual meeting of world's seven leading industrial nations. Then there is G20 group that refers to the platform of leading 20 nations having strong and emerging markets including China, India, Brazil and Saudi Arabia (BRICS). Then there is G2 group though that is not officially designated. Yet it is real and actually most decisive group of the world. It comprises just two countries I.e. America and China which together represent 40% of the global GDP and 50% of its military spending. G2 is not an alliance or a forum for discussions or decision making. Rather it represents the economic relationship and new rivalry between two superpowers of the world. Till recently, the two nations were thought to be bound together by their interdependence and integrated supply chains. For example, I Phones were designed in America but manufactured in China. Total trade between two countries in 2018 was $600 billion with US investment in China being $116 billion and reciprocally Chinese investment in US being $60 billion. But this mutual economic integration did not help in the convergence of interests in order to reduce the risks of conflicts. Consequently, 'WTO concensus' seems to have broken up and G2 stands fractured. Engagement is giving way to entanglement ---trade wars, conflicts over territorial claims, security issues, footholds in Indian ocean, arms race, economic models and ultimately for global primacy for the rest of the century. This conflict of interests between the two aggressive super powers is giving birth to a new cold war of the present century. This growing rivalry is being termed as the "Thuciydides Trap"; the concept of conflict between a dominant power and a rising power as suggested by an ancient military historian of Athens. The US design of global economic management has ben generally accepted between 1991 and 2008. But the trust in American model got evaporated after the Banking crisis in America in 2008 and resultant economic recession in Europe and adjoining countries. This crisis gave Chinese the opportunity to boast of their own model of autocratic or state capitalism.She openly professes the poorer countries that democracies have only perpetuated poverty whereas Communism has banished poverty.

America has already become what England was soon after the industrial revolution I.e. The Great Britain. Now China is working hard with fanatical enthusiasm to displace America from that position of primacy and occupy the seat herself. Presently she derives all the economic growth by becoming the greatest manufacturing hub or workshop of the world. She imports all the required raw materials, including rare elements, from different corners of the world and manufactures the products and sells them in the international market at affordable rates. Presently, she is the largest producer of steel, aluminium, computers and solar cells. Many countries including US are afraid to exploit solar energy aggressively simply because they will have to purchase the solar cells only from China and would indirectly boost her economy. Consequently, China has been able to create a foreign exchange reserve of $3 trillion. When GDP is measured by the exchange rates, US economy is still larger than that of China. But Chinese economy becomes the largest when measured in terms of purchasing power parity. The second limitation to growth of China is that it does not have its own sufficient resources of oil and gas and meets the 75% demand of petroleum by importing from different countries. She desperately needs gas supply because thermal power plants have caused stifling air pollution. So need for a stable international demand for Chinese goods and machinery and heavy dependence on imported oil and gas compels her to weave a very delicate foreign policy as she wants friendly relations with some countries and punish others who do not fall in line with her thinking and ideology. When Chinese killed our 50 soldiers in Ladakh two years back, people of India raised a hue and cry to boycott the use of Chinese products. Immediately, Chinese newspaper Global Times issued threats against the concept of Swadeshi Jagran and Indian government did not show the guts to support the people to boycott the Chinese products and Chinese exports to India remained stable at $90 billion per annum.

Now China has embarked upon a massive international project i.e. Economic integration with the world nations. This project has three purposes.

A. To reduce the transport distances from exporting countries.

B. To maintain the two way traffic of exports and imports with the rest of the countries on a sustainable basis.

C. To neutralise the American efforts to contain the rise of Chinese influence.

A. Reducing the distances.

China has to import oil, gas and other raw materials from different countries and these products have to be brought by sea by travelling very large distance. For example, oil has to be brought from Saudi Arabia and the ship has to come by Malluca straits and South China sea to reach Shanghai port. Then part of it has to be transported again from east end to the west end. To mitigate this problem, China initiated a mega project of constructing a sea port at Gawadar at the Pakistan

sea coast and a Highway from Gawadar to the Chinese border through Pakistan at a cost of $60 billion. China gave a big loan to Pakistan to develop an economic corridor along the highway. This passage will reduce the travel time of import items by half. China has also embarked upon large road and railway projects to have direct connectivity with Middle East and countries of Eurasia and Central Europe. Another highway project is under construction to link Laos and seven other countries up to Malaysia.

Another major project is One Belt One Road or Silk Route Road Project along the old silk route of olden days. The purpose of this project is to have an exclusive major Rail-road Highway together with gas-oil pipelines and electric transmission lines from China to the last European country. Another purpose of these alternate connectivity projects is to achieve strategic security. This is because that presently, all the Chinese ships have to pass through Mallucca straits near Singapore and that is under American control. In case of conflicts with America, all Chinese sea routes would be choked and hence the need for building alternative routes.

B. Maintaining two-way highway of exports and imports.

China meets 75% of its crude oil requirements from various oil exporting countries. The demand for gas has also increased tremendously as a clean fuel to replace coal as a major source of energy. China does not want to depend entirely on Middle East countries as suppliers of crude oil. Soviet Russia is the second main exporter of oil and gas after the Middle East countries. But Russia had the tendency to arm twist or leverage the recipient countries for the supply of crude oil. After the break up of Soviet Russia in 1991, many new countries were borne. These countries now constitute Eurasia. These countries are surplus with both oil and gas. Kazakhstan is nearest to China and has ample source of gas and oil both. All these countries maintain their independent foreign policy and no longer work under Russian hegemony. So main thrust of China is to build durable infrastructure projects to ensure sustainable supply of oil and gas to ensure energy security for a very long time. Likewise China is mining lot of raw materials from west African countries to keep the engine of growth running. Also China has to sell her products constantly to clear the stocks of the manufacturing hub to avoid the possibility of over saturation of finished products. Obviously, these highways will serve the purpose of maintaining two-way traffic of imports and exports. Therefore construction of new highways linking various countries with China has become an essentiality for China and she is working on these projects very laboriously.

C. Neutralizing the American influence.

America is not sitting idle. She is taking two steps to contain Chinese influence. She is spending huge amounts to modernise its naval force because all the flash points of possible US-China conflicts are in the neighbourhood of China (Taiwan for example) and far away from America. So annual defense spending of America is $650 billion against Chinese $ 250billion. The third and fourth spenders on defense are Russia and Saudi Arabia with an annual spending of $ 65 and $60 billion respectively. The second step is to regroup nations who are traditionally against the expansionist, aggressive , intimidating and muscular foreign policy, communism and untrustworthy friendship and commitments (like that of Hitler) of China and creat blocks to undercut Chinese hegemony over weaker nations under various pacts like NATO. For example QUAD (US,Australia Japan and India) is one block to stop Chinese influence in the Indian Ocean.AUKUS is another. Most countries are mortally frightened of China like Ceylon and India. But they can look straight into the eyes of Xi Xinping once they get American backing.China has started taking steps to counterbalance this approach.

China is now not only flushed with money but is also in a position to transfer technology of any kind to other nations. She contacts highly underdeveloped nations with rich mineral resources (mostly west African countries) and offers them loans to build infrastructure projects like highways, dams, universities, mining etc and executes those projects with the help of her own engineers and technicians. Presently, the World Bank gives loans only for green projects like solar energy development or climate change. The Chinese government also ensures that she will not bother for internal issues like dictatorship, human rights violation. In return, she obtains rights to take up projects that suits her interests. Secondly, she offers loans to developing countries along with technology support in order to create market for her finished goods. The main focus is now on Eurasian countries like Ukraine and South-east Asian countries like Indonesia. Some countries are grabbing this loan facility but others do not take the bait fearing that China would be entangling them in a debt trap. The example of Ceylon is cited quite often. When Ceylon could not pay off the loan, China compelled the government to hand over the Habentota sea port on 99 years lease. China had taken up this project to have a naval base in the Indian Ocean. But government of India applied enough pressure on Sri Lanka to put a rider that the port would not be used for strategic purposes. Now China is thinking of making the loan terms more attractive.

The crux of the whole discussion is that Chinese government is working relentlessly to spread her economic tentacles in as many countries as possible to creat an economic empire of her own with the tools of economic (but not armed) aggression to create a position of primacy like that of Great Britain after the Industrial Revolution.

To sum up, China of Xi Xinping is not the China of Deng Xinping anymore. Xi has launched the third revolution and amended the Constitution considerably and has made himself the life President of China like Vladimir Putin. He has launched the operation of demolishing all that Deng Xinping stood for namely open door policy, market friendly reforms, growth of private sector. He has now indulged in over use of hubris and invectives, picking up quarrels, bullying the nations and cutting the wings of private sector and growth of public sector.He abhors billionaires. There were 387 billionaires when he took over the administration in 2013. 235 additional billionaires grew till 2020. Now the number should start shrinking because of the crackdown as he perceives billionaires as hidden threat to his throne. Real Estate giants like Evergrade are on the brink of bankruptcy. Their buildings and townships constructed in violation of green technology and building bye-laws are being razed to the ground with the help of explosives. Now he openly tells that his dream is to make Communism as the global order of administration. Next few years are worth watching for the success or downfall of the third revolution.

Russia:-

Soviet Union was broken up into 15 nations in 1991. Russia was still a big country with 140 million population and vast Siberian icy desert with huge reserves of oil and gas underneath. But Russian economy received a temporary set

back due to the break up. There was political instability for some years. Finally Vladimir Putin became the President and days of political instability were gone for a very long period. Putin is now President of Russia till 2036. Many Russian believed that break up was engineered by America in order that gas and oil from the new born countries could flow towards Europe at easy terms and also America and western Europe could invest in these countries to extract oil and gas to reduce her dependence on Middle East countries and attain energy security on a sustainable basis. This assumption was partly true.

Russia was worried not so much for the fall in economic parameters as for the prestige of being the super power at the international forum. The world was happy because break up resulted into the end of Cold War between US and Russia. Putin could resurrect her economy but not the position of primacy. Quick economic recovery was possible because Russia was in a position to earn foreign exchange because of sale of oil, gas and arms. Now she needed two things to achieve the twin objective of consolidation of economic strength and international primacy of pre break-up days.

Firstly, she tried to frame a union of all the 15 break up nations to create a privileged sphere with invisible Russian hegemony. European Union also tried to include these new born nations into her fold. Both sides ended with partial success. Then Russia made the mistake of annexing Crimea and part of Ukraine in her territory. This aggressive posturing annoyed both US and European Union who clamped large number of sanctions against investment in that country. This step further stunted the economic growth of Russia. The second step was to find buyers for her gas, oil and arms. She tasted her first major success when Germany agreed to collaborate in the 1365 miles long gas pipeline to transport Russian oil into Germany. Germany also went ahead for laying the second pipeline. America greatly resented the laying of second pipeline. President Trump used very harsh words agaist the German Prime Minister Mrs. Angela Merkel. He even went to the extent of saying," What is the use of NATO if Germany is getting economically integrated with Russia." But Merkel brushed aside all these allegations and went ahead with the project.

Russia met another big technological success when a Russian oil and gas Company discovered gas in Yamal Peninsula in the northern most part of Siberia. This place is only 300 miles away from North Pole and lies in the Arctic Circle. The temperature here is -43 degree F during winter with no sunlight during the day. Likewise there is no darkness during the summers. Obviously extraction and transport of gas in containers up to the sea is a very difficult job.

Putin had to visit China along with a group of advisors Ministers to clinch a $400 billion hard bargain to supply LNG gas to China for 25 years. The 1865 miles pipeline ,called Siberia Power Pipeline, has been laid and commissioned to transport Yamel Peninsula gas to China. The total cost of this project is $30 billion. China shared 40% of the total cost.

Putin also framed the strategic or geopolitical alliance with China to fight jointly to constrain the increasing influence of America particularly in the Asia-Pacific region.. In other words, Russia has reconciled to the third position of being a superpower in the world with first two position grabbed by America and China. Now five countries of Central Asia broke up from Soviet Union namely, Kazakhstan, Kyragistan, Tazikstan, Turkmenistan and Uzbekistan (total population of all five being 72 million) are called the pivot or heart of the world. China has started investing heavily in these five countries to execute various infraprojects and to create market for her goods.

India:-

Today India is placed in a very delicate geopolitical position. On the northern side, there is hostile and aggressive China. On western side, Pakistan is as inimical as ever. (Imran Khan sincerely wanted to improve relations with India when he took over as Prime Minister. But India did not respond because of domestic political reasons.) Thereafter, hostility continued to grow and is still growing. The rule of Talibans in Afganistan has further increased the intensity of a hostile and insidious environment around India. This is because of two reasons. Firstly, the vacuum created by the withdrawal of American troops has been filled by China and Pakistan. China has already given a loan of $330 million to Afganistan. Secondly, in response to the formation of QUAD (group of US, India, Australia and Japan), China has formed the trans Himalayan QUAD among Nepal, Pakistan, Afganistan and China as a retaliatory measure. This new QUAD presents ominous portends for India. China is now planing to virtually colonize these three poor countries and reducing them to the status of vassal states. This is because, these countries are starving for foreign assistance and that is available with China only. International loaning agencies like World Bank have virtually refused to grant loans to these countries. China, like Russia, always leverages (even arm twists) the loaning facility to derive maximum advantage. Now China has started the construction of Peshawar-Kabul Highway.

Another serious geopolitical or geostrategic problem is cropping to India's disadvantage. India has been able to keep very good relations both with Russia and America till recently. But not anymore now after joining the QUAD(Quadrilateral) group. Russia has virtually agreed to play second fiddle to China to challenge the rising influence of America. India signed a $ 5.4 billion deal to purchase S-400 missiles from Russia and the first tranche of equipment will be arriving in India in November this year. America now calls India her partenership to checkmate Chinese influence for the sake of stabilising democratic forces and world peace. Unofficially, she treats India her ally like any other NATO country after forming the QUAD. As a result, America cannot tolerate any of her ally to purchase Russian or Chinese goods particularly the arms. This happened when German Prime Minister Morkel went ahead in laying the second gas pipeline between Russia and Germany and ignored the veiled threats of President Trump. Now President Biden is giving top priority to frame and implement the agenda of both QUAD and AUKUS (separate group of US, UK and Australia to form additional security ring in Indo-Pacific region to contain Chinese expansionist tendencies). This is clear from the recent one to one meeting between Indian Prime Minister and American President to be soon followed by the visit of Wendy Sherman (the US Deputy Secretary of State) to India. She made three important statements in India. Firstly, that relations with India are of paramount importance to America. Secondly, S-400 air defense system is dangerous for the security of the recipient country and US will be imposing sanctions under the American law. Thirdly, Chinese policy of economic integration with underdeveloped countries is nothing but economic coercion. Therefore S-400 deal with Russia is under threat once US imposes sanctions against its import. Consequently, Sherman

had detailed discussions with Harsh Verdhan Shringla and Ajit Doval to settle this issue. The net outcome of these discussions is not known. This is how the very future of non-aligned policy of India is under serious strains.

Non-aligned policy of India had stood the test of time. Once Dr. Ram Manohar Lohia had remarked in a parliamentary debate that India's non-aligned policy was like the adage " Ganga gaye Gangadas aur Jamna gaye Jamnadas; America gaye Amriki Mitter aur Roos gaye Roosi Mitter." This policy has remained as such till now. But after joining QUAD, it is under serious threat.

Indian Prime Minister had formed a good bonding with Chinese President Xi Xinping who visited India twice and showed lot of warmth. But the new found friendship started showing cracks very soon when China did not criticise Pakistan for giving succour to terrorists and India opposed the Chinese mantra of economic integration called "One Belt one Road (BRI)" when all other SARRC nations had endorsed it wholeheartedly. Xi Xinping had advised our Prime Minister saying," India and China are two big markets of the world and the two countries should work unitedly to promote greatness of Asia and block the western influence as future belongs to ASEAN countries." It meant that India should align with China in competing with American geopolitical interests. India did not agree and Xinping decided to teach India a lesson and is working incessantly to achieve that objective. Needling India with border skirmishes and occupying strategic points along the LAC is part of that strategy and design. Indian and Chinese soldiers had a face off in the sensitive Tawang sector of Arunachal Pardesh in the first week of October 2021. That our Prime Minister was mortally frightened of Xi Xinping was in evidence when Chinese soldiers killed 50 soldiers of Indian army in June 2019 at Ladakh border. The Prime Minister took 36 hours to react to this ghastly incident and still did not dare to accuse China by name. The situation may be different after joining the QUAD.

Now world energy market is on fire because OPEC countries have refused to increase the oil production to pre-Covid levels. On the other hand, there is big spurt in the demand of oil consumption due to coming winter. Consequently, there is every likelihood of oil prices crossing the $80 per barrel mark. Indian economy is going to be seriously affected due to this price surge. High price and falling rupee (I.o$=Rs.74.75) are definitely going to generate tail winds to accelerate inflation.

India imported 204 mt of crude oil (82% of the total demand) at the whooping cost of Rs. 6.7 lac crore in 2018-19 when the price was around $55 per barrel. Likewise, India is purchasing LNG from Quatar at huge cost. India could not develop oil and gas resources in a significant way indigenously inspite of the much trumpeted open licence exploratory program during the last two decades. Likewise the overseas arm of ONGC cut much ice in creating new oil resources oversease. Therefore heavy import bill due to purchase of hydrocarbons is a great drain on foreign exchange reserves and widens the gap of trade deficit. Also the issue of energy security remains unresolved. Only aggressive exploitation of solar energy and hydropower and electrification of transport system can save the situation.

एक ही पहचानिए, असमानस की जात !

– डॉ० धर्मचन्द्र विद्यालंकार

वर्तमान हमारा कृषक समाज धार्मिक अथवा सांस्कृतिक रूप से चौराहे पर ही खड़ा हुआ है। क्योंकि एक ओर यदि वह आर्य समाज से पूर्णतया प्रभावित रहा है तो दूसरी ओर वह सनातनी हिन्दूत्व से भी ओतप्रोत रहा ही है। हालांकि उस की मूलभूत प्रबल प्रवृत्ति वैदिक आर्य–धर्म की ओर ही अब तक रही है। जिस का प्रतिनिधित्व प्रबलतापूर्वक वर्तमान में आर्यसमाज ही करता है। क्योंकि मूल वैदिक धर्म में भी कहीं पर भी अवतारवाद और उस के आधार पर प्रचलित प्रस्तर–प्रतिमा पूजन भी नहीं थे। वे तो आर्य पुरोहितों किंवा वैदिक ब्राह्मणों ने बौद्ध और जैन–धर्म से ही पूर्व मध्य काल में उधार लिये थे। वरना किसी भी वेद–शास्त्र अथवा दर्शन में इन अवधारणाओं की पूर्व में प्रावधान कहाँ है।

परन्तु फिर भी वेदों को ऋषिकृत या मानवों द्वारा रचित मानने की बजाय उनको ईश्वरीय कृति मानना अथवा उनको अपौरुषेय और आप्त ज्ञान–ग्रंथ मानना जैसी मूल मान्यताएँ वैदिक धर्म या आर्यसमाज की भी तर्कसंगत कहाँ है। दूसरे, वैदिक वर्ण–व्यवस्था की विभाजक सामाजिक संरचना भी आर्य–धर्म की अतार्किक एवं न्याय –संगत कहाँ है। जोकि ब्राह्मण वर्ण की सर्वश्रेष्ठता को स्वयंसिद्ध करती है। यदि वर्ण–व्यवस्था किवांजन्मजात जाति–व्यवस्था को वैदिक धर्म में से निकालकर बाहर कर दिया जाए तो उसमें ओर एकेश्वरवादी एवं समतामूलक इस्लाम में बहुत कम अन्तर है। तब केवल धर्मग्रंथ के रूप में वेद मूलतः तो एकेश्वरवादी और निर्गुणोपास कही है।

यहाँ पर यह कहना असंगत नहीं होगा कि अपनी आजीविका को ही अबाध बनाये रखने की गरज से वैदिक मतावलम्बी ब्राह्मण–पुरोहितों ने जैनों और बौद्धों से मूर्तिपूजा और उस के मूलाधार अवतारवाद को उधार लिया था। वरना वैदिक पुरोहित कभी यही कहा करते थे कि–

"हस्तिना ताड्य मानोधपि न गजेत् जैन मन्दिरम्,
न पठेत यावनी भाषा, प्राणैः कण्ठ गतैरपि।''

अर्थात् "खूनी हाथी से सबल सामना होने पर भी आत्मरक्षार्थ जैनों के मन्दिरों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर निर्जीव अथवा जड़–पूजा होती है। इसी प्रकार से प्राणों को संकट में देखकर भी यवन और मलेच्छों की भाषाएँ नहीं पढनी चाहिएँ।'' परन्तु बाद में इन्हीं वैदिक ब्राह्मण देवताओं ने श्रमण–संस्कृति को अप ने अगाध उदर में खा–पचाकर उसी नवीन धर्म–धारा का ही नव नामकरण 'हिन्दू–धर्म' किया था। वरना उस से

पूर्व वह वैष्णव अथवा भागवत धर्म ही तो कहा गया है पुराणों में। और तो क्या, 'गीता–माता' तक का पूरा नाम श्रीमद्भागवद् गीता ही है जोकि महाभारत के भीष्म–पर्व का ही परिशिष्टांश है और पाँचवी शताब्दी अथवा गुप्तकाल में ही विरचित है। क्योंकि वहाँ पर उस का रचनाकाल तभी बताया गया है जबकि वेद तीन की बजाय चार हो गए थे और विधाएँ चौदह से बढ़कर चौंसठ तक हो गई थी। अतएव यह कालक्रम चौथी–पाँचवीं शताब्दी का ही प्रतीत होता है। पूर्व मध्यकाल में अथवा आठवीं शताब्दी से लेकर बारहवीं शताब्दी पर्यन्त भारत वर्ष में एक व्यापक सांस्कृतिक संक्रमणया अतिक्रमण यह हुआ है कि नवोदित राजपुत्र–शक्ति का सबल राज्याश्रय पाकर द्विज देवताओं ने श्रमण–संस्कृति का समूल स माहार अप ने अगाधउदर अथवा हिंदुत्व में कर लिया था।

हिन्दू धर्म मूलतः ब्राह्मण धर्म ही तो है क्योंकि उसमें जो जटिल और कुटिल कर्मकांडों का बोलबाला है, वह उन्हीं की आजीविका को अजस्ररूपेण अबाध बनाये रखने का ही तो आध्यात्मिक उपक्रम है। भले ही मूर्ति–पूजा का प्रथम प्रावधान श्रमण–संस्कृति में प्रारम्भ हुआ था। लेकिन वहाँ उनके ऊपर लक्ष्मी–वर्षा कहाँ होती थी अथवा उनको साक्षात् तथागत बुद्धया महाबीर के ही जीवन्त विग्रह कहाँ माना जाता था। बौद्ध–धर्म का जो महायान सम्प्रदाय सातवीं शताब्दी में सम्राट हर्ष के शासन–काल में चलाया गया था। उसी में सर्वप्रथम प्रस्तरपूजा की प्रतिष्ठा हुई थी। क्योंकि तब बौद्ध–धर्म और दर्शन के क्षेत्रें में भी ब्राह्मण वर्ण का ही वर्चस्व काय म हो चला था। क्योंकि वसुबन्धु और असंग एवं दिंगनाग से लेकर नागार्जुन तक सारे ही तो बौद्ध–दार्शनिक वही थे।

अत एव आठवीं–दसवीं शताब्दियों में भारत के पश्चिमोत्तर से विदेशी अरबों एवं अफगानों के आक्रमण का भयभाव दिखाकर ही तो विप्रों ने बौद्धों के मठों को मन्दिरों में परिवर्तित कर लिया था। आज भी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चारों ही मठ मूलतः वही तो हैं। क्योंकि मठ, चैत्य, स्तूप और बिहार जैसी संरचनाएँ बौद्ध–भिक्षुओं की ही थीं। तो मन्दिर और स्थानक जैन–धर्म की ही सांस्कृतिक संरचनाएँ थी। ब्राह्मणों के तो केवल निर्जन वन–प्रान्तर में स्थित, गुरुओं के आश्रम या फिर गुरुकुल ही तो थे। अतएव अरब आक्रमण की आपदा को ही उत्तम अवसर में बदलकर आर्यपुरोहितों ने दक्षिण के शासक सुधन्वा और बंगाल के शासक, शंशाक की सशक्त सैन्य–सहाय तापाकर ही तो उन्होंने श्रमण संस्कृति के सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों पर अपना अबाध और एकक्षत्र अधिकार जमा लिया था। वही ब्राह्मण अथवा पौराणिक सनातन धर्म ही वर्तमान का हिन्दू धर्म है। और तो क्या, उस में सनातन जैसा विशेषण भी बौद्धों का ही है–''एत्थुधर्म स त्रनातनः'' ।

इसी पूर्वमध्य काल किंवा हिंदूकालयापि फरराजपूत–काल में ही भारतीय समाज में जन्मजात जाति–व्यवस्था कठोर हुई है। इसी काल में ब्राह्मण वर्ण का वर्चस्व समाज में और भी अधिक बढ चला था क्योंकि नवोदित राजपूत राजशक्ति का सबल सहाय तथाकथित इस सनातन; सड़ातन संस्कृति को मिल गया था। तभी तो उस में सती–प्रथा जैसी कुप्रथा प्रचलित हुई थी तो बालिका–वध भी इसी काल में आरम्भ हुई थी। पर्दा–प्रथा से लेकर बाल–विवाहों तक का सूत्रपात इसी हिन्दू या राज पूत–काल में जाकर हुआ था। नारी–शिक्षा का निषेध एवं विधवा–विवाहों का विरोध भी तो इसी पूर्व मध्य काल की अघट घटनाएँ हैं। एक पुरुष चाहे जितने विवाह अपने जीवन–काल में रचा सकता था, लेकिन एक बाल–विधवा स्त्री को पुर्नविवाह का अधिकार हिन्दू धर्म–धुरन्धरों ने नहीं दिया था। क्योंकि मनुस्मृति में यह स्पष्ट आदेश है कि–''न हि नारी पुर्नविवा हमहर्ति' अर्थात् स्त्री–मात्र को पुर्नविवाह का अधिकार उपलब्ध नहीं है। केवल अकेले इसी नारी–जाति विरोधी धर्मादेश के आधार पर ही हिन्दू समाज सवर्ण और अवर्ण में भी बाँट दिया गया था। जो भी जातियाँ विधवा–विवाह की प्रबल पक्षधर थीं, वहीं अवर्ण और अछूत अथवा वर्णशंकर; व्रात्य तक मान ली गई थी। वार्ता, कृषिकर्म को भी संस्कृत में कहा गया है। उस को अपने हाथों से करने वाली और पुर्नविवाह की परम पावन वैदिक व्यवस्था का अपने प्राणपण से पूर्णत या परिपालन करने वाली जाट–गूर्जर–आभीर–लोधे–कुर्मी–कोइरी–कुशवाह–मौर्य–माली–मराठा जैसी मध्य किसान जातियों को उपर्युक्त इन्हीं दो आधारों पर ब्राह्मण धर्म–शास्त्रकारों ने व्रात्य अथवा दासीपुत्र और शूद्र तक सिद्ध कर दिया था। सुमति भार्गव नामक ब्राह्मण द्वारा मनु के नाम से रचित मनुस्मृति में तभी तो यह कहा गया है–

> "शनकैस्तु क्रियालोपादिमा क्षत्रिय जातयाः
> वर्षलत्वं गतालोके ब्राह्मणानामदर्शनात्।।"
>
> (मनु–39–40)

अतएव इसी नवीन हिन्दू धर्म किंवा सनातन धर्म की उपर्युक्त क्रूर एवं कठोर धर्म शासनाओं के विरोध में ही तो गुरु गोरखनाथ जैसे सन्त सिपाहियों ने अपनी आवाज उठाई थी। समतामूलक इस्लाम का भी सहारा निर्गुवादी अथवा निराकारोपासक सिद्ध और नाथों को मिल गया था। क्योंकि केश्वरवादी इस्लाम में भी मूर्तिपूजा और अवतारवाद के लिए अवकाश कहाँ था। फिर वहाँ पर वैदिक वर्ण–व्यवस्था की विकृति –जातिव्य वस्था के बन्धन भी उतने कठोर कहाँ थे। अतएव निगुर्णिया सन्त–साहित्य के सृजन की पृष्ठभूमि में आचार्य हजारी प्रसाद जैसे उद्भट विद्वानों ने भी यह सत्य स्वीकार किया है कि यदि भारत में इस्लाम न भी आता तो भी भारतीय समाज बारह आना वही रहता।" यहाँ पर

अर्थाप्राप्ति से यह स्पष्ट है कि अधिक न सही कम–से–कम चार आने का अर्थात् एक चौथाई या पच्चीस प्रतिशत समाज के दलित और पिछड़े वर्गों पर तो एकेश्वरवादी और निर्गुणवादी इस्लाम का प्रभूत प्रभाव हुआ ही है।

अतएव सन्त साहित्य के सृजन के पीछे आन्तरिक और बाहरी दोनों ही प्रकार की प्रेरणाऐं और परिस्थितियाँ प्रभावशाली रही हैं। गुरु गोरखनाथ ऐसे प्रथम भारतीय धर्माचार्य हैं, मध्य पूर्वकाल के जिन्होंने ब्राह्मण–धर्म के बाह्य आडम्बरों के सर्वप्रथम चुनौती दी थी। तभी तो उन्होंने मूर्तिपूजा का नितान्त निरसन करने के लिए ही आन्तरिक निराकार उपासना पर अतिरिक्त बल दिया था–

"पण्ड़ित ध्यावै देहुरा, मुसलमान मजीद,
जोगी ध्यावै अलख को, जहँ देहरा ममजीद।''

(गोरख–संहिता)

भक्ति आन्दोलन के प्रथम और प्रखर प्रस्तावक सन्त कबीर भी तो गुरु गोरखनाथ से ही पूर्णतया प्रभावित थे। उनकी एक रचना भी 'गोरख–गोठठी' के नाम से मिलती है। अतएव कबीर ने ही सर्वप्रथम मूर्तिपूजा और अवतारवाद एवं जन्मजात जाति–व्यवस्था का खुलकर विरोध किया था। उन्हीं की विचार–परम्परा में रैदास, नानक, धन्ना और पीपा एवं दादूदयाल और गरीबदास जैसे सन्त आते हैं।

सद्गुरु कबीरदास ने ही सर्वप्रथम मूर्त्तिपूजा से लेकर तीर्थ स्थानों की पवित्रता तक पर उंगली उठाई थी। उन्होंने छापा–तिलक और माला एवं पूजा के आड़म्बरों के अम्बारों पर प्रश्न खड़े किए थे। बजाय बाहरी दिखावों के उन्होंने आंतरिक आत्म–साधना पर ही अपना अतिरिक्त बल दिया था–

"जल बिच मीन पियासी, सुनत में आवत है हाँसी,
आत्म–ध्यान बिना सब झूठा, कहा मथुरा कहा कासी।"

इसी प्रकार से उन्होंने ही जन्मजात आधार पर सर्वप्रथम ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार नहीं किया था, बल्कि मानव–मात्र की एकता और समानता का ही शंखनाद किया था–

"जो तू ब्राह्मन, बामनी का जाया,
आन बाट ते क्यों नहीं आया।

गुरु नानक ने तो प्रत्येक प्राणी में उसी एक ईश्वर के दिव्य प्रकाश का साक्षात्कार अपनी बाणियों में किया है–

"अल्ला–अव्वल नूर उपाया, कुदरत के सब बन्दे,
एक नूर तै सब जग उपज्या, कौन भले कौन मंदे।"

और भी कहा, "एक ही पहचानिए, अस मानस की जात।"

इस प्रकार से गुरु–ग्रन्थ साहब में सद्गुरु कबीर से लेकर सन्त रविदास और धन्ना–भगत जैसे निगुर्णिया सन्तों की सारी ही वाणियाँ संकलित है। अतएव सिखमत एक प्रकार से पूर्णतः सन्त–मत ही है। जोकि मानव–मात्र की एकता और सामाजिक समानता के ही अटूट अभिलाषी थे। इस प्रकार से हम यह भी देखते हैं कि सिखमत में न तो मूर्त्ति–पूजा का ही आड़म्बर है और न ही अवतारवाद का दिखावा है। बल्कि वहाँ पर जन्मजात जाति–पाँति का भेदभाव भी कहाँ है। क्योंकि वहाँ पर गुरुद्वारों में जो संगत और पंगत की जो परम पावन परम्परा प्रचलित है, वह सामाजिक समर सता की भी सहज साधक है। इस्लाम की भाँति सिखमत में भी एक साथ बैठकर भोजन और भजन या अरदास करने की जो स्वतंत्रता सभी को उपलब्ध है, वही उनकी संगठन की शक्ति और सेवा एवं सम्पूर्ण समर्पण की भी सच्ची साधना है।

वर्तमान के किसान–आंदोलन में हमने यही पाया है। अतएव वर्तमान में मध्य–किसान जातियों के सम्मुख अब दो ही विकल्प विद्यमान हैं। एक स्वस्थ और सबल विकल्प उनके सम्मुख इसी समतामूलक सिखमत या सन्त–मतका है तो दूसरा एक और विकल्प श्रमण संस्कृति को अपनाने का भी है। क्योंकि वहाँ पर भी मनुष्य मात्र की एकता और समानता की संकल्प ना है। बौद्ध–धर्म दर्शन में ही अंगुलिमाल जैसे क्रूरकर्मा दस्युराज को संघ में शामिल करने का उन्मुक्त अवसर मिला था। उसी प्रकार से आम्रपालि जैसी वार–वनिता का अनन्त उद्धार भी श्रमण संस्कृति ने ही किया था। पुराणों में बाद में जो उदारता हिन्दू धर्म ने अजामिल और शबरी के लिए दर्शाई है, वह श्रमण–संस्कृति की सहनशीलता और समन्वय शीलता का ही पावन प्रतिप फल था।

इसी प्रकार से जैन धर्म से निकले हुए मानी धर्म के प्रथम प्रवर्तक वृषभनाथ और पार्श्वनाथ ने ही कृषि–कर्म एवं व्यापार–वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया था। जिसका पावन प्रभाव पूरे ही पश्चिम एशिया (ईरान–इराक) तक भी हुआ था। फिर जैन धर्म का शाकाहार, अस्तेय (चोरी न करना) अपरिगृह; अति संचय न करना एवं अनेकान्तवाद जैसे ही सिद्धान्त महानतम जीवन–मूल्य भी हैं। विशेषकर अस्तेय और अपरिग्रह पूँजीवाद और सामन्तवाद के विरोधी हैं तो अनेकान्तवाद किंवा स्याद्वाद विचारों की स्वतंत्रता का ही सबल समर्थन करता है। क्योंकि जैन–दर्शन यही मानता है कि सत्य सदैव बहुआयामी ही होता है। वह कदापि एक आयामी या इकहरा नहीं होता। अतएव हमें अप ने विरोधी विचारों में भी सत्यांश का संधान करना चाहिए।

जनतांत्रिक व्यवस्था के दो ही महान मूल्य समता और स्वतंत्रता है। यदि बौद्ध–धर्म मानवमात्र की एकता और सामाजिक समानता का सहज साधक है तो जैन–धर्म व्यक्तिगत वैचारिक स्वतंत्रता का सबल समर्थक है। जबकि ब्राह्मणया हिन्दू धर्म में ब्राह्मणों का वचन ही जर्नादन का वचन है। वहाँ पर केवल

ब्रह्म–वाक्य ही आप्त प्रमाण है। फिर ब्राह्मण और क्षत्रियों तथा वैश्य जैसे वर्णों का विद्यायाज्ञान शक्ति–बल और धन–सम्पदा पर जो एकाधिकार अधिमान्य गीता जैसे धर्म–शास्त्रें में किया गया है, वह सर्वथा समता और स्वतंत्रता एवं न्याय के अनुकूल कहाँ है। अतः अन्ध राष्ट्रवाद सभी प्रकार की सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं की अनदेखी करने का ही तो उपक्रम है। वैसे भी हिन्दू धर्म में स्वर्ण स्वामियों का ही प्रभुत्व धन–धरती और सेवाओं तक पर है। उद्योग–धन्धों पर भी उनका ही एकाधिकार है। अतएव वहाँ पर पूंजीवाद और सामन्तवाद का ही सतत् शोषण बना रहेगा तो ब्राह्मणवादी पुरोहितवादी वर्चस्व भी बना रहेगा। चाहे वह हिन्दू राष्ट्रवाद के नाम पर हो या राममंदिर निर्माण के नाम पर। वह हिन्दू मात्र की एकता का ही अनवरत आलाप करके किसानों और मजदूरों को पूँजीपतियों का ही पूँछ पडा हुआ पिच्छलग्गू बनाए रखेगा। श्रमिक वर्गों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रता और स्मृद्धि त्रिकाल में भी संभव कहाँ है। हमने वर्तमान के किसान–आन्दोलन की अनवरत उपेक्षा से यही अनुभव किया है। नोटबंदी जब विगत वर्षों में एकाएक लागू हुई थी तो करोल–बाजार, दिल्ली के सेठों ने उस के विरोध में अपना सार्वजनिक रूप से शक्ति–प्रदर्शन किया था। एक दिन के उस लघु प्रदर्शन की बाँकी झाँकी देखकर ही भारतवर्ष के लौह–पुरुष अश्रुविगलित हो उठे थे। दूसरी ओर मध्य किसान जातियों के किसान विगत सात–आठ माह से फूंस की ठिठुरती ठंड में दिल्ली के दुर्ग द्वार पर बैठे हुए हैं। लेकिन उनसे सार्थक संवाद स्थापित करने का भी अवसर दिल्ली के स्वयं भू सम्राट के पास क्यों नहीं है।

सवर्ण हिन्दू समाज के प्राणधन और धर्म में ही तो सदैव बसते हैं। अतएव क्रान्तिकारी किसान या तो धन की चोट मारकर पूँजीपतियों की इस हृदयहीन सरकार को जगा सकते हैं। या फिर वे धर्म–परिवर्तन करके ही सवर्ण समाज की सहानुभूति प्राप्त कर सकते हैं। मध्य किसान जातियों द्वारा श्रमण–संघ में सम्मिलित होने से उनकी शक्ति और भी अधिक बढ़ जाएगी। क्योंकि लगभग बीस–पच्चीस प्रतिशत दलित और अति पिछड़े भूमिहीन किसान और कामगार एवं खेतिहर मजदूर भी उनके ही संग–साथ श्रमण–संघ में शामिल हो सकते हैं। दूसरी ओर सिखमत की ओर जो विशेष झुकाव हम वर्तमान में विशेषकर जाट–किसानों का देख रहे हैं। वह उनकी हरियाणा–पंजाब से लेकर पश्चिमी उ०प्र० और उत्तराखंड से लेकर राज स्थान तक जातीय एकता को ही सुदृढ़ करेगा। लेकिन चौधरी छोटूराम और चौ० चरणसिंह से लेकर चौ० देवीलाल तक का अपनाया हुआ 'माजगर–संघ' का सूत्र और भी अधिक सशक्त सिद्ध हो सकता है। यदि उस में मुस्लिम किसान भी जुड जाएँ तो वह 'अजगर–संघ' तो राष्ट्रीय स्तर पर और भी अधिक शक्तिशाली राज नीतिक स्तर पर हो सकता है। जाटों के सिख–मत में समाने पर क्या उपर्युक्त दोनों ही संघों के निर्माण में भी उन्हें सफलता मिल सकती है, यह निर्णय काल–देवता ही करेगा। वैसे वर्तमान में तो उनकी दशा और दिशा 'तीन में न तेरह' वाली ही है, फिर भी वह जाति किसान–वर्ग की सशक्त ईजन तो है ही।

वैवाहिक विज्ञापन

- SM4 Jat Girl (DOB 23.08.98) 23/5'4" B.Sc. Non-Medical, MA. English, Doing B.Ed. Father ASI in Chandigarh Police. Mother housewife. Family settled in Chandigarh. Avoid Gotras: Singhmar, Nehra, Beniwal. Cont.: 9417753780
- SM4 Jat Girl (DOB 25.10.92) 29/5'4" B.Tech (Electrical & Communication). Working as Contact Engineer in Bel company. Family settled at Pinjore. Avoid Gotras: Dhayal, Punia, Phogat. Cont.: 9416270513
- SM4 Jat Girl 34/5'2" B.Tech (CSC) Employed as Senior Delivery Manager (Software Developer) in MNC Chandigarh with Rs. 22 lakh PA. Avoid Gotras: Jaglan, Gahlan, Kadyan. Cont.: 7837113731
- SM4 Jat Girl (DOB 06.02. 92) 29/5'3" Master in Economics and B.Ed. Employed as teacher in Manav Rachna International School Mohali. Avoid Gotras: Nain, Panghal, Sangwan, Dhaliwal. Cont.: 8699726944, 7009399930
- SM4 Jat Girl 25/5'5" CSE from P.U. Chandigarh. Employed as P.O. in BOI. Avoid Gotras: Ahlawat, Lohchab, Balhara, Rathi not direct. Preference Tri-city based family and at least equal status. Cont.: 9417378133
- SM4 Jat Girl (DOB 88) 33/5'3" M.A. (Economics), PhD. (Economics) NET cleared. Working in "Niti Aayog" New Delhi. Father class-II officer retired from Haryana Govt. Brother settled in USA. Avoid Gotras: Dahiya, Sehrawat, Jatrana. Cont.: 9988224040
- SM4 Jat Girl (DOB 01.01.96) 25/5'4" Post Basis BSc. Nursing 2nd year. Avoid Gotras: Brach, Bhophia. Cont.: 9988440565
- SM4 Jat Girl (DOB 04.05.90)31/5'5" B.Tech(Electrical & Communication). Employed in Indian Railways as ASTE (Assistant Signal & Telecommunication Engineer) at Sealdah (Kolkatta). Avoid Gotras: Kulria, Khicher. Cont.: 9416342608
- SM4 Jat Girl (DOB 02.07.90) 31/5'3" B.C.A. from Punjab University. Working in Chandigarh Administration. Avoid Gotras: Dagar, Ohlyan, Dhundwal. Cont.: 9041505150, 8968539993
- SM4 Jat Girl (DOB 28.08.91) 30/5'2" M.Sc. (Math), MSc.

Psychology (Gold Medalist) P.G. Diploma in Guidance & Counseling). B.Ed. (CTET-PRT & TGT) (APS-CSB-PRT). Working as Assistant Professor contractual. Father Retired Kanoongo. Mother housewife. Avoid Gotras: Rathi, Jhanjhariya, Rohz, Direct Ahlawat, Pawar. Cont.: 9992075101

- SM4 Jat Girl (DOB 22.08. 87) 34/5'6" M.Sc. (Physics) M. Tech. (Material Science & Engineering). PhD Chemistry. Working as Guest Faculty in Delhi University with 8 lakh LPA. Got Doctor scholarship from Science & Technology Department. Father retired from Govt. job. Mother housewife. Avoid Gotras: Rathi, Kuhar, Mann. Cont.: 9466568539
- SM4 Jat Girl (DOB 14.05.98) 23/5'5" M.Sc. (Physics). Doing B.Ed. Avoid Gotras: Khatkar, Lohan, Dhull. Cont.: 7986168202
- SM4 Jat Girl (DOB 28.03. 2000) 21/5'4" M.Sc. (Non-Medical) Doing B.Ed. Father Govt. Teacher. Mother housewife. Avoid Gotras: Khatkar, Lohan, Dhull. Cont.: 7986168202
- SM4 Jat Girl (DOB 25.01. 97) 24/5'6" M.Sc. (Chemistry) B.Ed. Avoid Gotras: Khatkar, Sheoran, Sohlat, Thakan. Cont.: 9888518198
- SM4 Jat Girl (DOB 15.09.95) 25/5'5" B.Sc (Micro-Biology), M.Sc. (Micro-Biology) from K.U.K. Preparing for I.A.S. Father retired from Govt. Job. Agriculturist landlord. Mother housewife. Family settled at Jagadhri (Yamuna Nagar). Avoid Gotras: Sheoran, Chahal. Cont.: 9518680167, 9416036007
- SM4 Jat Girl 29/5'2.5" B.Tech, MBA, IIM working EY Banglore. Salary 24 Lakh. Avoid Gotra: Malik, Bidhan, Bidhan. Cont.: 8194945551
- SM4 Jat Girl 29/5'4". B.A. from Kurukshetra University. GNM from Pt. Bhagwat Dayal University Rohtak. Preferred match from Tri-city. Avoid Gotras: Bankura, Mann, Narwal. Cont.: 9354839881
- SM4 Jat Boy (DOB 01.02.94) 27/6'2" Employed as Assistant in Indian Post Department at Panchkula. Avoid Gotras: Mann, Gehlayan, Chhikara. Cont.: 9416276670
- SM4 Jat Boy (DOB (13.04.87) 34/6'2" M.A. Public Administration, LLB from CLC Delhi University. Advocate, Practicing in Delhi. Father Additional Chief Secretary retired from Govt. of India. Mother Lecturer retired from Haryana Government. Elder brother married and working as Manager in Indian Overseas Bank. Avoid Gotras: Ahlawat, Malik, Sangwan. Cont.: 9417496903, 9023187793
- SM4 Jat Boy (DOB 22.02.95) 26/5'11" B.Tech. Working in TCS Co. at Delhi with package of Rs. One lakh PA. Father ASI in Chandigarh Police. Mother housewife. Family settled in Chandigarh. Avoid Gotras: Singhmar, Nehra, Beniwal. Cont.: 9417753780
- SM4 Jat Boy (DOB 91) 30/5'6" B.Tech. Working in I.T. MNC Co. with package of Rs. 19 lakh PA. Father retired from Government service. Family residing in own house at Panchkula. Preferred Tri-city/Delhi NCR working girl in IT MNC. Avoid Gotras: Ruhella, Dahiya. Cont.: 7206328529
- SM4 Jat Boy (05.01.93) 28/5'8" B.Tech (Mechanical). Working as group- C employee in Govt. of India, Department of Central Water Commission at National Water Academy, Pune. Father Haryana Government employee. Mother housewife. Avoid Gotras: Kaliraman, Panghal, Punia. Cont.: 9992394448
- SM4 Jat Boy (20.04.91) 30/5'8" B.Tech (Computer Science). Own business, with Sparrow GG Solutions_OPC Pvt. Limited. Income Rs. 6 lakh PA. Mother Assistant in Haryana government. Avoid Gotras: Kadyan, Ahlawat, Dagar. Cont.: 9876855880
- SM4 Jat Boy (DOB Oct. 92) 29/6'2" B.Tech (CSE), M.S. (Business Analytics). Working as Product Manager in MNC at Chandigarh with Rs. 40 lakh package PA. Family settled in Panchkula. Avoid Gotras: Bhambhu, Sangwan, Mohil. Cont.: 9464259180
- SM4 Jat Boy 30/5'8" B.Tech from Kurukshetra University. Working in MNC Company at Banglore with Rs. 26 lakh package PA. Avoid Gotras: Malik, Khatri, Dahiya. Cont.: 9463491567
- SM4 Jat Boy (DOB 22.10.92) 29/5'11" B.Tech (Electronics & Communication) Working in H.S.S.C. on contract basis. Father retired Under Secretary. Family settled in own house at Panchkula. Avoid Gotras: Nehra, Rathi, Duhan, Hooda. Cont.: 9417347896
- SM4 Jat Boy (DOB 30.09.93) 28/6'2" Bachelor of Arts with Math and Economics from P. U. Chandigarh. Passed two Post graduate diplomas in Event Management & Global Hospitality Management from Canadian College. Avoid Gotras: Phougat, Dahiya, Rathi. Cont.: 9915484396
- SM4 Jat Boy (DOB18.10.90) 29/6'1" B.Tech from P.U. Chandigarh. Working as Inspector in CBI. Father retired as Under Secretary. Preferred working match in Central Government. Avoid Gotras: Khasa, Dahiya, Lathwal, Mor. Cont.: 9023492179, 7837551914
- SM4 Jat Boy (DOB 04.10.88) 32/6'1" B.A., LLM Working as Legal Consultant in Law Firm at Chandigarh with Rs. 30000 PM. Father Class-I officer retired. Mother housewife. Family residence at Panchkula and Sonepat. Avoid Gotras: Malik, Jhanjharia. Cont.: 9876155702
- SM4 Jat Boy (DOB 28.05.93) 28/5'8" B.A., Employed in Bharat Electronics Limited Panchkula on contract basis. Avoid Gotras: Kundu, Phogat, Ruhil. Cont.: 7696544003
- SM4 Jat Boy (DOB 01.01.94) 27/5'3" B.Tech., MBA.,

Marketing. Businessman. Avoid Gotras: Dahiya, Kajla, Halawat. Cont.: 9463881657

- SM4 Jat Boy (DOB 09.06.93) 28/5'8" Diploma in Civil Engineering. Employed in Indian Air Force X Group (Corporal). Father Retired Kanoongo. Mother housewife. Avoid Gotras: Rathi, Jhanjhariya, Rohz, Direct Ahlawat, Pawar. Cont.: 9992075101
- SM4 Jat Boy (DOB 05.11.97) 23/6'1" B.Tech. (Mechanical). Employed in Chandigarh Administration on regular basis. Father Sub. Inspector in Haryana Police. Mother housewife. Preferred match with job in tri-city. Avoid Gotras: Nayotne, Bhadhran (Goyat), Panjeta. Cont.: 9467412702
- SM4 Jat Boy (DOB 10.08.88) 32/5'9" B.Tech. (Mechanical). Working as Training Officer, GITOT Rohtak. Avoid Gotras: Kharb, Rathi, Khatri. Cont.: 9416152842
- SM4 Jat Boy 28/6'2" Captain in Army. District Yamuna Nagar (Haryana). Avoid Gotras: Darri, Sindhad, Sindhu. Cont.: 7717397230
- SM4 Jat Boy (DOB 27.04.89)31/5'10" B.Tech.in Bio-Medical Engineering. Working in a reputed Master's Medical Company with package of Rs. 16.5 lakh PA. Father businessman. Mother housewife. Avoid Gotras:Jatyan, Duhan, Dagar. Cont.: 9818724242.

सी.बी.एस.एम स्पोटर्स स्कूल निड़ानी में सम्मान समारोह कार्यक्रम करवाया

गांव निड़ानी के चौधरी भरत सिंह मैमोरियल स्पोटर्स स्कूल में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस समारोह में नार्वे में हुई विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप में सिल्वर मैडल विजेता अंशु मलिक और कांस्य पदक विजेता सरिता मोर को सम्मानित किया। सी.बी.एस.एम स्पोटर्स स्कूल निड़ानी में आयोजित सम्मान समारोह के मुख्यतिथि प्रदेश के पूर्व डीजीपी डॉ महेन्द्र सिंह मलिक और सी.बी.एस.एम स्पोटर्स स्कूल निड़ानी संस्था की चेयरपर्सन कृष्णा मलिक रही। इस मौके पर नार्वे कुश्ती चैंपियनशिप की सिल्वर मैडल विजेता अंशु मलिक को जाट सभा चण्डीगढ़ और सी.बी.एस.एम स्पोटर्स संस्था की तरफ से 51 हजार रुपये और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं कांस्य पदक विजेता सरिता मोर को 41 हजार रुपये और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक एवं सी.बी.एस.एम स्पोटर्स स्कूल के संरक्षक डॉ. महेन्द्र सिंह मलिक ने कहा कि खिलाड़ियों को सम्मान ही देश का सम्मान है। क्योंकि उनके स्कूल की खिलाड़ी अंशु मलिक पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मैडल के लिए मुकाबला लड़ा हैं। हालांकि

जुलाना: सिल्वर मैडल विजेता अंशु मलिक को सम्मानित करते हुये पूर्व डीजीपी डॉ० महेन्द्र सिंह मलिक और संस्था चेयरपर्सन कृष्णा मलिक।

अंशु मलिक को सिल्वर मैडल ही हाथ आया हो लेकिन सिल्वर मैडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। वहीं सरिता मोर ने कांस्य पदक जीता हैं। ऐसे में दोनों खिलाड़ियों ने देश व प्रदेश का नाम रोशन किया हैं। इसलिए केन्द्र व प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह दोनों खिलाड़ियों सम्मानित करें। डॉ. महेन्द्र सिंह मलिक ने कहा कि भारतीय महिला खिलाड़ियों के चीफ कोंच कुलदीप मलिक को भी अभी तक पदोन्नती तथा सम्मानित नहीं किया हैं जो कि बड़े खेद की बात हैं।

हमें जिन पर गर्व है

जाट सभा चंडीगढ़/पंचकूला के आजीवन सदस्य, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग हरियाणा में कार्यरत वैज्ञानिक इंजीनियर श्री भूप सिंह पंवार की सुपुत्री कुमारी अंकिता पंवार ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित परीक्षा में 321वां स्थान प्राप्त कर शानदार सफलता हासिल की। इन्होंने इससे पूर्व 2 वर्ष तक बैंग्लोर में ओरेकल में साफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर काम किया। अंकिता पंवार को वर्ष 2011 व 2013 में उनकी शानदार शैक्षणिक सफलता पर जाट सभा द्वारा सम्मानित किया जा चुका है।

जाट सभा चंडीगढ़, पंचकूला एवं चौधरी छोटूराम सेवा सदन कटरा–जम्मू के समस्त सदस्यगण अंकिता पंवार को उसकी उत्कृष्ट/उल्लेखनीय सफलता पर बार–बार बधाई देकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।

आर्थिक अनुदान की अपील

आपको यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि जाट सभा चंडीगढ़ द्वारा 6 जून 2019 को गांव कोटली बाजालान-नोमैई कटरा जम्मु में जी टी रोड़ पर 10 कनाल भूमि की भू-स्वामी श्री संतोष कुमार पुत्र श्री बदरी नाथ निवासी गांव कोटली बाजालान, कटरा, जिला रियासी (जम्मु) के साथ लंबी अवधि के लिए लीज डीड पंजीकृत की गई है। इस भूमि का इंतकाल भी 6 जुलाई 2019 को जाट सभा चंडीगढ़ के नाम दर्ज हो गया है। इस प्रकार इस भूमि पर जाट सभा चंडीगढ़ का पूर्ण स्वामीत्व स्थापित हो चुका है। बिल्डिग़ के मजबूत ढ़ांचे/निर्माण के लिये साईट से मिट्टी परीक्षण करवा लिया गया है और बिल्डिंग के नक्शे/ड्राईंग पास करवाने के लिये सम्बन्धित विभाग में जमा करवा दिये गये है। इसके अलावा जम्मु प्रशासन व माता वैष्णों देवी साईन बोर्ड कटरा को यात्री निवास साईट पर जरूरी मूल भूत सार्वजनिक सेवायें - छोटे बस स्टैड़, टू-व्हीलर सैल्टर, सार्वजनिक शौचालय, वासरूम, पीने के पानी का स्टाल आदि के निर्माण हेतु पत्र लिखकर निवेदन किया गया है। यात्री निवास स्थल पर ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी (बी.डी.पी.ओ.) कटरा द्वारा सरकारी खर्चे से दो महिला एवं पुरूष स्नानघर व शौचालय का निर्माण किया जा चुका है और पानी के कनैक्शन के लिये भी सरकारी कोष से फंड मंजूर हो गया है और शीघ्र ही पानी की आपूर्ति का कनैक्शन चालू हो जायेगा।

जाट सभा द्वारा यात्री निवास भवन का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने का प्रयास था लेकिन कोविड़-19 महामारी के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका और इस महामारी का जाट सभा की वित्तीय स्थिति पर भी प्रभाव पड़ा है। जाट सभा चण्डीगढ़/पंचकूला यात्री निवास भवन का निर्माण करने पर वचनबद्ध है और शीघ्र ही निर्माण शरू कर दिया जायेगा।

यात्री निवास भवन का शिलान्यास व दीन बंधु चौधरी छोटू राम की विशालकाय प्रतिमा का अनावरण 10 फरवरी 2019 को बसंत पंचमी उत्सव एवं दीन बंधु चौधरी छोटूराम की 136वीं जयंती समारोह के दौरान महामहिम राज्यपाल, जम्मु काश्मीर माननीय श्री सत्यपाल मलिक द्वारा तत्कालीन केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीएमओ डा0 जितेंद्र सिंह व जाट सभा के अध्यक्ष एवं हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक डा0 एम एस मलिक, भा0पु0से0 (सेवा निवृत) की उपस्थिति में संपन्न किया गया।

यात्री निवास भवन एक लाख बीस हजार वर्ग फुट में बनाया जाएगा जिसमें फैमिली सुईट सहित 300 कमरे होगें। भवन परिसर में एक मल्टीपर्पज हाल, कांफ्रेंस हाल, डिस्पैंसरी, मैडीकल स्टोर, लाईब्रेरी, बच्चों की प्रतिभा विकास एवं विभिन्न व्यवसायिक व सुरक्षा संबंधी सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग की विशेष सुविधाएं उपलब्ध होगीं। सुरक्षा सैनिकों, शहीद परिवारों व उनके आश्रितों के लिए मुफ्त ठहरने तथा माता वैष्णों देवी के श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएगीं। यात्री निवास के निर्माण के लिये श्री राम कंवर साहु सुपुत्र श्री पूर्ण सिंह, गांव बीबीपुर जिला जीन्द (हरियाणा), वर्तमान निवासी मकान नं0 110 सुभाष नगर, रोहतक द्वारा 5,11,111/- तथा श्री सुखबीर सिंह नांदल, निवासी मकान नं. 426-427, नेमी सागर कालोनी, वैशाली नगर, जयपुर द्वारा 5,01,000 रुपये की राशि जाट सभा, चण्डीगढ को दान स्वरूप प्रदान की गई है।

आप सभी से नम्र निवेदन है कि इस कल्याणकारी व पुनित सामाजिक कार्य के लिए स्वेच्छा अनुसार शीघ्र अनुदान देने की कृपा करें ताकि निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जा सके जोकि आज सभी के सहयोग से ही संम्भव हो सकेगा। यदि कोई दानी सज्जन यात्री निवास में कमरे के निर्माण हेतू 5 लाख रूपये या इससे अधिक की राशि दान देता है तो उसका नाम भवन परिसर में उचित स्थान पर अंकित किया जाएगा और उसे भवन में आजीवन मुफ्त ठहरने की सुविधा प्रदान की जाएगी। जम्मु काश्मीर के भाई-बहन व दानवीर सज्जन इस संबंध में चौधरी छोटु राम सेवा सदन के अध्यक्ष श्री सर्बजीत सिंह जोहल (मो0नं0 9419181946), श्री भगवान सिंह उप प्रधान (मो0नं0 8082151151) व केयर टेकर श्री मनोज कुमार (मो0नं0 9086618135) पर संपर्क कर सकते हैं। यात्री निवास भवन के लिए अनुदान देने वाले सज्जनों का उचित विवरण रखा जाएगा और उनका नाम जाट सभा द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका 'जाट लहर' में भी प्रकाशित किया जाएगा। भवन निर्माण की अनुदान राशि चैक, डिमांड ड्राफट द्वारा 'जाट सभा चंडीगढ़' के पक्ष में जाट भवन 2-बी, सैक्टर 27-ए, मध्य मार्ग, चंडीगढ़ में भेजी जा सकती है अथवा आर टी जी एस की मार्फत सीधे जाट सभा के बचत खाता नंबर 50100023714552, आईएफएससी कोड- एचडीएफसी 0001324 में ट्रांसफर की जा सकती है।

अनुदान की राशि आयकर अधिनियम की धारा 80-जी के तहत आयकर से मुक्त है।

निवेदक : कार्यकारिणी जाट सभा चंडीगढ़/पंचकुला,
चौधरी छोटू राम सेवा सदन, कटरा, जम्मू

सम्पादक मंडल

सरंक्षक एवं सम्पादक : डा. एम.एस. मलिक, आई.पी.एस. (सेवानिवृत)

सह–सम्पादक : डा॰ राजवन्तीमान

साज सज्जा एवं आमुख : श्री आर. के. मलिक

प्रकाशन समिति : श्री बी.एस. गिल, मो॰ : 9888004417

श्री जे.एस. ढिल्लो, मो॰ : 9416282798

वितरक : श्री प्रेम सिंह, कार्यालय सचिव, जाट भवन, चण्डीगढ़

जाट भवन 2–बी, सैक्टर 27–ए, चण्डीगढ़

फोन : **0172–2654932 2641127**

Email: jat_sabha@yahoo.com; Website: www.jatsabha.org

सर छोटूराम जाट भवन, सैक्टर–6, पंचकूला

फोन : 0172–2590870, **Email: jatbhawan6pkl@gmail.com**

चौधरी छोटू राम सेवा सदन, कटरा, जम्मू

Postal Registration No. CHD/0107/2021-2023 **RNI No. CHABIL/2000/3469**

मुद्रक प्रकाशन एवं सरंक्षक सम्पादक डा. एम. एस. मलिक ने जाट सभा, चंडीगढ़ के लिए एसोशियटिड प्रिन्टर्ज़, चंडीगढ़, फोन : 0172–2650168 से मुद्रित करवा कर जाट भवन, 2–बी, मध्यमार्ग, सैक्टर 27–ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित किया।